कारण भारतीय गणराज्य में निरन्तर जनता में आग्नेय अस्त्रों का वितरण किया जाना है।

सरकार यदि चाहती है कि अपराधों में कमी हो भय व आंतक का वातावरण समाप्त हो, शोषणकारी शक्तियां निर्मूल हों, तो अविलम्ब आग्नेय अस्त्रों एवं आयुधों के वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये प्रभावकारी कदम उठावें और आयुध अधिनियम को संशोधित करें ताकि केवल आग्नेय अस्त्र सुरक्षापन्तियों के हाथों आरक्षी क्षेत्रों में ही सीमित रहें, एवं अवैधानिक रूप से फैलने वाले आग्नेय अस्त्रों पर रोक लगे व पकड़ हो सके।

12.33 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1982-83 *(contd.)*

MINISTRY OF HOME AFFAIRS – *Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER : The House will not take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs. I would like to announce that the Minister of State for Home Affairs will intervene in the debate at 3 p.m. and the Minister of Home Affairs will reply to the debate at 5.15 p.m. Now Shri Godil Prasad Anuragi will continue his speech. Since he has already taken 9 minutes, he is entitled to take another one or two minutes.

श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह-मंत्री का ध्यान केस्तरा कांड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 7-1-82 को हरिजनों के घर में वहां के रावतों ने रात को जाकर आग लदा दी। वे लोग रात को वहां पर सोना बाई और देवन्तीन बाई की इज्जत लूटने की नियत से घुसे थे। वहां पर उन्होंने आग लगा दी। सोना बाई और देवन्तीन बाई वहां से भाग निकलीं और नांदघाट थाने में रिपोर्ट के लिये पहुँचीं। उनके घर में जो रावत लोग घुसे हुए थे वह उनके 8 बोरा धान और 200 रुपये लेकर आये। इस घटना की रिपोर्ट के लिये जिस समय सोना बाई और देवन्तीन बाई नांदघाट में आई तो वहां के थानेदार **जी और हवलदार **ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और उनको बुरी-बुरी गालियां दीं। अन्त में सोना बाई और देवन्तीबाई ने निवेदन किया कि महाराज हमको घर पहुँचाने के लिये कोई कोतवाल या पुलिस दे दीजिये। उस समय **ने यह कहा कि **मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस बात को सुनकर रोते हुए देवन्तीन बाई और सोना बाई अपने पति हेमप्रसाद और जमुना प्रसाद के पास आई और उनको सारी बात बताई। इसके बाद** हवलदार 3 दिन के बाद वहां पहुँचा। उस समय वहां पर गंगा प्रसाद, जमुना प्रसाद और डेरहू प्रसाद उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि हमारी धर्मपत्नी को आपने** कहा था,** उस समय ** ने कहा कि तुमको मैं कुछ दिन के बाद गर्दन कटवा दूंगा।

इसका परिणाम क्या निकला कि 24-1-82 को वहां के रावतों से सांठ-गांठ कर के केदार सतनामी के घर चढ़ाई की गई। चढ़ाई के समय उनको ललकारा गया कि आओ, आज तुमको हम मारने आये हैं। ऐसा कहते हुए वहां के ** आदि ने घातक हथियारों से गंगा प्रसाद पिता केदार, हेम प्रसाद वल्द गंगाप्रसाद और जमुना प्रसाद

**Expunged as ordered by the Chair.

[श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी]

वल्द केदार, मथुरा प्रसाद, रंजित वल्द गंगा प्रसाद और रुकमंड वल्द गंगा प्रसाद आदि को घातक हथियार से मार दिया।

मुझे यह भी बताया गया कि वहां पर बन्दूक और पिस्तौल की भी आवाज निकली इन सारी की सारी घटनाओं को सोनाबाई और देवन्तीन बाई अपनी नज़रों से देख रही थीं। जब उनकी बारी आई तो सोना बाई और देवन्तीन बाई ने रोदन करते हुए कहा भाइयो, आप हमारे बच्चों को गोद ले लीजिए, आप हमें मार लीजिए, मगर आप इन बच्चों को छोड़ दीजिए। लेकिन उन कसाइयों ने उस मां की ममता की तरफ ध्यान न देते हुए उन छोटे छोटे बच्चों, चन्द्रसेन और शिवकुमार, को मार दिया और उसके बाद उन्हें जलती हुई आग में डाल दिया।

वहां पर सीताबाई और शान्ति बाई नाम की दो छोटी लड़कियों को भी घातक हथियारों से मार दिया गया। वहां पर स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा बच्चा इन सारी घटनाओं को देख रहा था वह किसी दूसरे घर में भाग गया। उन रावत हत्यारों ने उसे भी वहां से खींच कर जलती हुई आग में डाल दिया।

रेशम बाई अपनी आंखों से इन 13 परिवारों की हत्या को देख रही थी। उस अबला ने हाथ जोड़ कर कहा कि भाइयों कुल के दीप जलाने के लिए मेरे गर्भ में जो बच्चा है, उसको आप छोड़ दीजिए। परन्तु उन हत्यारों ने घातक हथियार से उसके पेट पर वार किया, जिससे पेट के अन्दर बच्चा भी कट गया, और मां पृथ्वी पर लेट गिर गयी।

झाड़ से बंधी हुई पिलाबाई, जो कि केदार सतनामी की धर्मपत्नी थी, यह सब कुछ देख रही थी। उसको छुड़ा कर वे हत्यारे लाशों के पास लाए और कहने लगे कि यह लाश किस की है, यह लाश किस की है, और साथ साथ उसकी पिटाई करते रहे। हरिजनों के साथ इस तरह का अमानुषिक व्यवहार किया गया।

जब गंगा, जमुना और केदार ने देखा कि हमारे जानो-माल की सुरक्षा नहीं होने वाली है, तो उन्होंने जा कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, थानेदार †† और अनुविभागीय अधिकारी को लिखित रिपोर्ट दी कि हमारी जान-माल और इज़्जत संकट में है, आप हमारी रक्षा कीजिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार वहां पर होम गार्ड के चार सिपाहियों को भेजा गया। नियम और कानून कहता है कि जिस अधिकारी ने उन्हें भेजा था, उसी अधिकारी के हुक्म से उन्हें वापस बुलाया जा सकता था। लेकिन थानेदार †† ने 15 तारीख को उन्हें वापस बुला लिया।

वहां के हरिजनों पर अमानुषिक ढंग से अत्याचार हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि नादघाट पुलिस विभाग ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ सांठ-गांठ कर के और उनके पैसे से मतवाले हो कर हरिजनों की हत्या करवाई है। मैं मांग करता हूं कि इस मामले की सी० बी० आई० से जांच करवाई जाए और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। †† सब-इन्सपैक्टर, थाना नांदघाट, अनुविभागीय अधिकारी †† अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और †† हवलदार पर धारा 302 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए।

†† Expunged as ordered by the Chair.

मैं हिन्दू धर्म के ठेकेदार चारों जगतगुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वरों और गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि समय रहते हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को न रोका गया, तो क्या हम हिन्दू धर्म को चाटते रहेंगे।

आप को याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अत्याचार होने पर भीमसेन ने कहा था, "अरे, दुःशासन तुम ने द्रोपदी का चीर-हरण किया है, इस गदा से तुम्हारी भुजा उखाड़ेगा और उस खून से जब तक द्रोपदी अपने केश नहीं धोयेगी तब तक द्रोपदी अपने केश बांध नहीं सकती है।" भीमसेन ने एक प्रतिज्ञा और की कि "अरे दुर्योधन, तुम ने द्रोपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिये कहा है, जब तक तुम्हारी जंघा को मैं नही तोड़ दूंगा तब तक मैं भीमसेन नहीं कहाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और क्या कहूं, हम लोग बहुत दुखी हैं। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज हरिजनों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह आपको इस पगड़ी में सुनाई नहीं देता है और चश्मे से नजर नहीं आता है कि इसको कौन सी पार्टी करवा रही है। अगर आप जांच करवाये तो सही तथ्य आपके सामने आ जायेगा। हम लोग सदैव श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इन्दिरा जी के साथ ही मरेंगे, इन्दिरा जी के साथ जियेंगे इन्दिरा जी को हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिये कि इन्दिरा जी की बदनामी करने के लिये कुछ विरोधी दल के लोग षडयन्त्र कर के पुलिस के साथ सांठ गांठ करके हरिजनों की हत्या करवा रहे हैं। इसको सख्ती के साथ रोका जाना चाहिये।

हरिजन अपने अधिकार के लिये गांव के सार्वजनिक देवालय में जाता है तो उसकी मजदूरी बन्द कर दी जाती है। इसलिये दुखित होकर वह देवालय जाना ही छोड़ देता है।

शहर की गन्दी-गन्दी बस्तियों में हरिजन लोग कीड़े-मकौड़ों की तरह से रहते हैं। आप उनके लिये अनुदान दीजिये और उनके लिये मकान बनवाइये। टूटी-फूटी झोपड़ियों में उनको मत रहने दीजिये।

जहां तक अस्पृश्यता निवारण का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि हमारे हरिजनों में भी छुआछूत मनाई जाती है। अतः अन्य लोगों के लिये जो अस्पृश्ता-निवारण सम्बन्धी कानून लागू है वही हरिजनों पर भी लागू होना चाहिये। अगर कोई हरिजन छुआछूत मानता है तो उस पर भी एक हजार रुपये जुर्माना और एक साल की सजा होनी चाहिये।

सारे भारतवर्ष में हरिजनों के साथ भेद-भाव बरता जा रहा है। भेद-भाव को बन्द करना चाहिये। आज हरिजनों के नाम से बिजली ले ली जाती है लेकिन हरिजनों के मुहल्ले में बिजली नहीं होती है जिससे 95 प्रतिशत हरिजन अन्धेरे में रहते हैं। इस ओर भी आप को ध्यान देना चाहिये।

मैं माननीय गृह मन्त्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि आपने जितने भी बन्दूकों के लाइसेंस दिये हैं उन को निरस्त कर दीजिये तभी हरिजन सुरक्षित रह सकते हैं अन्यथा समस्त हरिजनों को भी आप बन्दूक के लाइसेंस दीजिये ताकि वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकें।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देते हुए गृह विभाग की मांग का समर्थन करता हूं।

*SHRI BAJU BAN RIYAN (Tripura East): Mr. Deputy Speaker, Sir, in the Report of the Home Ministry it has been stated that the law and order situation in the country is under control. But in reality we find that law and order in the country is deteriorating day by day. We should try to find out what is the reason behind this deterioration. I think that this Government is going to establish capitalist system in the country. The means of production are concentrated in the hands of a handful of persons, who are controlling the entire productive process of our country. All the strife and conflict is being caused day by day struggle for controlling and owning this machinery and means of production. This struggle is causing greatest harm to the tribals, the minorities, the harijans and other weaker sections. This year has been termed as 'the year of productivity.' It has been claimed that production in the country has gone up considerably. But we find that along with increase in production, disturbances and strifes are also increasing. Why is it so? It is because the production of the country is not being properly distributed. The distribution is faulty. A handful of big capitalists are cornering the lion's share of the production of the country. They are indulging profiteering and are causing rise in prices of all essential commodities. It is these people who are generating all disturbances and lawlessness. The Government is blind to all these. This system of production and distribution is having its effect on all sphres of our society. The harijans, the tribals and other weaker sections are the greatest suppress. Today, after 34 years of rule by vested interest in the country, we find that majority of the harijans, the tribals and the Scheduled Caste people are living below the poverty line. They constitute 25% of the population of this country. The people have been recognised as the weaker sections and there is special provision in our Constitution for providing facilities to these people so that there may be betterment and upliftment of these weaker sections. There is also provision in the constitution for preserving their cultural heritage. But the Government is not paying any attention to all these. This Government has not yet been able to formulate an effective compact scheme for the upliftment of Socio economic condition and for the preserving the cultural heritage of all the tribals and harijans in the country. Whatever steps they may have taken in this direction are all meant to provide temporary satisfaction to these classes so that they may be lured to cast their vote in favour of the ruling party to enable them to continue with their miserable Government.

Under the present Government we have seen that the harijans and the tribals have been uprooted from their lands and homes. Today they do not possess the same amount of land that they posessed earlier. Whatever facilities they earlier had for education, for preserving and enriching their own language and in matters of employment opportunities are getting reduced day by day. In spite special provisions in the constitution, in spite of job reservations for these people, we find that many posts under the Central Government have not been filled and on the other hand there is growing unemployment among these weaker sections. The harijans, the tribals, the Scheduled Caste people are rarely given employment in the Government and semi-Government establishments in any State of the country. Their quota of jobs remain unfilled. It is of course said that candidates with requisite qualification or experience could not be

*The original speech was delivered in Bengai.

found among these people. But I do not think that is correct or is a valid reason for denying employment to them. The Government wrongly claims that they have done much for the betterment of the harijans, the tribals and other backward people. The claim that much has been done under the earlier 20 point programme and more will be done for them under the new 20 point programme. But I do not believe that anything worthwhile will be done under these programmes also to enable the harijans, the tribals and the Scheduled Caste people to have a decent living. They being crushed under rising prices and growing unemployment. This is the gift of the present Government to these people. They are the most exploited class. This situation is being taken advantage of by the separatist forces in the country. They are showing the paths of separation. In the North-Eastern region, in Mizoram, in Tripura, in Nagaland, in Assam, in the tribal belts of Orissa, Bihar, Madhya Pardesh, West Bangal etc. Separatist organisations are raising their heads.

Somewhere they are called M. N. F. somewhere the P. L. O. and by some other name in some other area. These organisations are inducing and arousing these poor people to separate themselves from the democratic mainstream of the country and to separate States for their own betterment. This is a very dangerous trend and the Government should wake up to this danger.

Sir, our party believes that this trend of separatism is totally wrong. Sometimes the Government issues statements that the opposition parties do not cooperate with them in fighting these divisive forces. I want to say with all the force at my command that my party and the left front Government, wherever they are in power, e.g. West Bengal, Tripura etc. will lead all cooperation to the Central Government in their efforts to fight these divisive and separatist forces and also in all their efforts to fight poverty.

Sir, in Tripura we have formed the Tribal Areas Autonomous District Council through elections. It is aimed at bettering the socio economic conditions of the tribal people. I expect the Central Government to advance all help, financial, legal etc. needed by this council for improving the lot of the tribal people and of the other people of that area.

Sir, the Government of Tripura has given a local spoken kok-barak language the Status of State language. The West Bengal Government has also given the Nepali language and the Santhali language the status of State language. They have also taken steps to provide education in those languages. This has been done by the left front Governments running under the leadership of our party.

Sir, there are large number of harijans living all over the country. They may be in smaller sects. I will demand from the Central Government to provide all facilities for the development of their language.

I will also demand that even those language of our country which only exist as a spoken language and has not developed a written script yet, they should also be included in the Eighth Schedule and given all facilities for their development along with the other languages that are already in the eighth schedule.

Sir, the forests of our country were utilised by the tribal people in various ways. They also used to earn their livelihood from these forests. After the Government came to power, they created new forests

[Shri Baju Ban Riyan]

called 'plantations'. The forests were destroyed. The Government failed to protect the forests and the tribal people were uprooted from there. Large number of tribal people in Karnataka, Madhya Pradesh etc. have been uprooted from their forest habitations and have spread to other areas where they are reaming about like gypsies and even eating jackals for food. This is the plight of the forest people.

Sir, the minimum wages act has come into force. But it has not been implemented in all the States. The harijans and the tribals would have been the chief beneficiary if this act was implemented in all the States. In the economic Survey it has been admitted that more than 50% of our people live below the poverty line, This is the proof that the minimum wages act has not been implemented in all the States. A majority of those 50% people who live below the poverty line are tribals, harijans and S.C.S.T. people.

This Government has failed to protect the rights of the minorities also. In many places in the name of protecting them, the minorities have been forcibly uprooted.

Today we have read in the newspapers that in Tamilnadu there has been a fight between harijans and Caste Hindus. As a result some 22 persons have been killed or injured. This way we find that atrocities on the harijans and on the minorities continue unabated under the present Government. The Government is not bringing forth the necessary legislation for protecting them.

On the other hand the present Government is busy in changing the Ministers and Chief Ministers of various States. The portfolios of the Ministers are being changed frequently. There is no certainty who will hold charge of a particular Ministry and that too for how long. Everything is so chaotic. Even then, the Government claims that the situation is very stable in the country. The parties in the States are unable to choose their leaders who will form the Government Shrimati Indira Gandhi decides every thing for them. This is stability! Shrimati Gandhi will keep on deciding who will run the Government in which State ?

To combat this situation, all the working people of the country, the labour classes, all those who help to increase production, all the technicians scientists and intellectuals will have to come together and to wage a united struggle to overthrow the present Government and to form the left force oriented Governments and with that, Sir, I oppose the demands of the Home Ministry and conclude my speech.

13 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

गृह विभाग का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। इसको राष्ट्रीय एकता, सद्भाव और अपनापन देश के विभिन्न वर्गों में बनाये रखना होता है। हमारी सरकार 1980 में दोबारा शासन में आयी थी। उस समय की और अब की लॉ एण्ड आर्डर व्यवस्था को देखा जाए तो इस में हम उत्तरोत्तर सुधार पाते हैं। मैं इस विभाग के प्रतिवेदन के आंकड़े नहीं देना चाहता लेकिन उनसे यह पता चलता है कि जहां लॉ एण्ड आर्डर में सन् 1980 के पहले निरन्तर गिरावट हो रही थी वहां उत्तरोत्तर

अब सुधार हो रहा है। चाहे वह विद्यार्थी वर्ग का झगड़ा हो, लेबर मूवमेंट हो, सब में सुधार हुआ है।

अभी हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कहा कि असम, मणिपुर और त्रिपुरा में बड़ी जो कि भयावह स्थिति है नार्थ ईस्टर्न रीजन में है, लेकिन मेरा विचार है कि शांति बनाये रखने के हर तरह से वर्तमान प्रयास बेकार हुए हैं। इस सदन में हम सब यह जानते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर का विषय विभिन्न राज्य सरकारों का है। यहां की केन्द्रीय सरकार उस में सलाह और निर्देश देती है, तथा राज्य सरकारों की मांग पर अतिरिक्त फोर्स जो उसके आधीन है को भेजती है।

विभिन्न स्तरों पर जब राज्य सरकारें यहां से सहायता की मांग करती हैं तो केन्द्रीय सरकार अपनी फोर्स आदि भी भेजती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में राष्ट्रीय एकता और सद्भाव बनाये रखने के लिए केवल इसी से काम नहीं चलने वाला है। माननीय गृह मन्त्री जी के केवल यह कह देने से काम चलने वाला नहीं है कि लॉ एण्ड आर्डर प्रदेश सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार को यह भी देखना होगा कि जहां-जहां पर लॉ एण्ड आर्डर की विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है वहां वहां के लिए साधन भी जुटाये जाएं और स्थिति को वाच करें।

अभी आप जानते हैं कि कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों, हरिजनों पर अत्याचार हुए और वहां साम्प्रदायिक दंगे भी हुए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, विशेषकर वहां के मुख्य मंत्री ने दृढ़ता से वहां की परिस्थितियों का सामना किया। मैं यह भी कह सकता हूं कि पहले जितने साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे उनमें अब गिरावट आयी है और उनको कंट्रोल किया गया है। 1980 में मुरादाबाद से साम्प्रदायिक दंगा शुरू हुआ था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये दंगे अब बहुत कम रह गये हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार ऐसी प्रदेश सरकारों को सहायता दे ताकि वे सरकारें अपनी पुलिस की संख्या को बढ़ा सकें और दंगों को कंट्रोल कर सकें।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि पुलिस की मौजूदा ट्रेनिंग आदि में भी परिवर्तन हो। नई परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। आज देश की पुलिस को यह शिक्षा देनी होगी कि यदि देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करनी है तो हर जाति और वर्ग के लोगों को एक होकर रहना होगा। कुछ इस तरह की बटालियनें तैयार करनी होंगी, जिसमें हर जाति और वर्ग के लोग हों। इस ओर गृह मंत्री जी का ध्यान गया है और वे कार्य-वाही कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस कार्य में और तेजी लाई जाए। किसी एक वर्ग की कोई फोर्स न रह जाए और यह शिकायत न रहे कि किसी पुलिस फोर्स में किसी वर्ग विशेष के साथ पक्षपात हुआ है तभी साम्प्रदायिक दंगों पर काबू पाया जा सकेगा।

जनता पार्टी के समय में असम समस्या की जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार ने धैर्य से काम लिया है। विरोधी दलों का सहयोग लेने का भी प्रयास किया है, हालांकि विरोधी दलों के सहयोग को आपने देख ही लिया है। स्थिति में सुधार हुआ है और समस्या को हल करने के लिए सरकार कोई न कोई

[श्री राम प्यारे पनिका]

निर्णय राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर लेगी ही।

आदिवासी और हरिजनों की बातें इस गृह विभाग की मांगों पर हुई हैं। मैं आभारी हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आते ही और साथ ही साथ गृह मंत्री जी ने भी राज्यों को डायरेक्टिव्स दिए कि किस प्रकार से हरिजनों का कल्याण हो सकता है, किस तरह से उनका विकास हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर राज्य से इस बारे में रिपोर्ट मंगवाई जाए, इनके इंप्लीमेंटेशन के लिए एक अलग से सेल बनाया जाए कि जो डायरेक्टिव्स आपने दिए हैं, उन पर काम हो रहा है या नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत से राज्य उसमें पीछे रहे हैं। हरिजन-आदिवासियों के विकास के लिए 'ट्राइबल-सब प्लान' 'शेड्यूल-कास्ट कंपोनेन्ट प्लान' आदि में विभिन्न राज्य सरकारों को धन राशि दी गई है, लेकिन बैंकों से सहयोग प्राप्त न होने से उस राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरे जनपद मिर्जापुर में 1 करोड़ 31 लाख रुपया सन् 1980-81 एवं 1981-82 का पड़ा हुआ है और हरिजनों की 1200 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं। इसमें 10 प्रतिशत को भी बैंक ने ऋण नहीं दिया है। इसके फलस्वरूप गरीब हरिजनों को जो फायदा मिलना चाहिए था, उससे वे वंचित रह गए। इलाहाबाद बैंक को इस कार्य के लिए रखा गया है परन्तु उसका कार्य राष्ट्रीय नीति के विपरीत है। इस तरह से प्रधान मन्त्री जी का जो स्वप्न है वह पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना में 50 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का निर्धारित लक्ष्य है। इसलिए बैंकों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है। आपके कन्ट्रोल में जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनको आप स्वयं देखें कि किन राज्यों में उन कार्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है।

पिछले वर्षों में देश में विभिन्न शेड्यूल-कास्ट और ट्राइब्स की लिस्ट का रेशनलाइ-जेशन करने की बात चल रही है। 1967 में शेड्यूल-कास्ट अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वापिस हो गया, 1976 में भी पेश किया गया था, जनता पार्टी शासन काल में भी इस पर विचार हुआ और बाद में वह बिल लैप्स हो गया। अब स्थिति यह है कि छूटे हुए शेड्यूल-कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हो रही है। 13 आदिवासी जातियों की लिस्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ने भेजी है, और मध्य प्रदेश, बिहार में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की मांग के बावजूद यह मांग पूरी नहीं हो रही है, जबकि मैं स्वयं भी पिछले दो वर्ष से प्रयास करता आ रहा हूं। इसमें बियार जाति को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जन-जाति हैं और इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यन्त शोच-नीय है। जहां तक विकास का प्रश्न है, यह तब तक नहीं हो सकती, जब तक लिस्ट का रेशनलाइजेशन नहीं हो जाता। मैंने गृह-मंत्री जी से कहा था, वे राज्यों से सूचनाएं भी मंगा रहे हैं, लेकिन दो वर्ष गुजर गये हैं। इस समस्या को जल्दी से जल्दी निश्चित रूप से हल करें ताकि आदिवासियों को विकास कार्यों का लाभ मिल सके जैसाकि दूसरे प्रदेश के आदिवासियों को मिल रहा है।

जहां तक गृह मंत्रालय के सुरक्षात्मक कार्यों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि

उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने, विशेषकर विरोधी दल वालों ने सरकार पर निराधार आरोप लगाए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न अपराधों में कमी आई है। जनता राज में विभिन्न अपराधों की जहां संख्या 2 लाख 13 हजार 471 थी वहां अब वह घट कर 1 लाख 80 हजार के थोड़ा सा ऊपर है। हम देखते हैं कि दस्यु उन्मूलन अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने छेड़ा है उसमें उनके भाई तक को बलिदान देना पड़ा है। डकैत जो फ्रस्ट्रेटिड हैं वे अब इन हथकण्डों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 22 गैंग जो बड़े-बड़े थे उनका सफाया कर दिया गया है। 47 परसैंट डकैतियों की संख्या में कमी आई है। विभिन्न आरोप जो विरोधी दलों ने उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर लगाए हैं, वे निराधार तथा सत्य से कोसों दूर हैं। गृह मंत्री जी समय-समय पर हमारे उत्तर प्रदेश में जाते रहे हैं। उन्होंने भी हमारी कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और माँग करता हूं कि उत्तर प्रदेश को और धनराशि की सहायता दी जाए। जिससे सरकार पुलिस को दृढ़ता प्रदान कर सके।

आपको यह भी सोचना होगा कि आई० पी० एस० और आई० ए० एस० में जो टस्सल चल रही है वह गम्भीर है और उसे खत्म होना है। यह नहीं चलने देनी चाहिये। एडमिनिस्ट्रेशन को आपको ठीक करना होगा। जिनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी कठिनाइयों को आपको दूर करना होगा, जो दिक्कतें हैं, आपको देखना होगा कि वे क्यों हैं और वे कैसे दूर हों।

ला एण्ड आर्डर के बारे में मात्र यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह प्रदेश का उत्तरदायित्व है। इसको ठीक करने के लिए अधिक से अधिक धनराशि उनको आपको देनी होगी। जो विशेष समस्या वाले प्रदेश हैं, विशेष कठिनाइयों वाले प्रदेश हैं, जहां आज से नहीं परम्परा से डकैत सक्रिय हैं, उन राज्यों पर केवल जिम्मेदारी डाल देने से काम नहीं चलेगा। बल्कि उनकी सहायता करनी होगी। उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस डिमाण्ड का समर्थन करता हूं।

SHRI JAGDISH TYTLER (Delhi Sadar): I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Home Ministry's grants. But if you look around—I am making a very valid point and 90% of the time the Opposition has been making a lot of noise that there is no law and order in the country—when this important debate is going on, there are only six members on the Opposition Benches and they are all persons who want to speak. Sir, this is the kind of interest the senior leaders of the Opposition are trying to show. Next time when they make a noise in the Parliament that the law and order situation is not all right in the country, they are not telling the correct position. They are making a mockery of this Parliament. They are interested that only their voice should be heard so that their names may come in the papers.

In our country dynamic social changes are taking place. The population is going up and with the increase in population, social changes are also taking place. Naturally the problems are also coming. Problems come out of disparity and a longing for equality and most of the problems

[Shri Jagdish Tytler]

come because of ignorance, falsehood and in the end, due to lack of education. Some of the problems had existed before the Independence and some of the problems still exist and some of the problems will exist. But how far can we put these problems right and how can we co-operate with the Government because we are all part and parcel in putting these problems of the country right. I will put the problems in three categories. Problems stem from economic corruption, administrative corruption or political corruption. Political corruption and economic corruption can be put right. But what about the administrative corruption ? Everybody speaks that politicians are corrupt, that businessmen are corrupt but have they ever thought of the bureaucrats ? Our Prime Minister has given the 20 point programme. I want you to make a note of this. Who are the people who are going to implement the programme ? Are we to implement it ? Is the Home Ministry going to implement it ? No, Sir. It is the bureaucrats who are going to implement it. Who are those bureaucrats ? They are the same bureaucrats who, in the three years of the Janata rule showed disrespect to our Prime Minister and who spoke against her and who spoke nasty things against her. How do you expect them that they will accept Mrs. Gandhi's 20 point Programme heartily ?

On administrative corruption, I want to speak. If you look round the country and if you look round the most beautiful colonies that were coming up in Delhi, Bombay, Madras and Calcutta, most of these colonies are the biggest colonies, the richest colonies, which were the most sought after colonies. Who are the owners ? The owners are the bureaucrats. In my constituency, a colony has been there for the last 20 years. It came up much before the Anand Niketan and Vasant Vihar colonies. This colony does not have the basic amenities. Developing charges had been paid for this colony. But, look at this Vasant Vihar colony, the most uptodate colony. Who is owning this ? Every house there is owned by a bureaucrat. Do you know the rents that they are getting ? They range from Rs. 10,000 to 25,000. They come and cry that they carry a salary of over Rs. 1500. With this they have to take care of their children.

They have to send their children for their education to the Convent schools. They have to send their children to the colleges. But, with this salary they cannot look after them. Ask them : these top bureaucrats, children go to the Convent schools, Public Schools. Every top bureaucrat's children study in the best colleges. They go to the foreign countries. When they retire, ninety per cent of them are taken in the U. N., the World Bank and other World Bodies. Who is corrupt ?

To-day, you will see so many times the Minister coming and speaking in the House, giving a chit to them. What they do is that they give the Ministers beautiful rooms and beautiful sofas and they put the Ministers there. It is they who formulate the policies. The Ministers simply come and read them out in Parliament. I shall give you one example. I have taken up a case for the last two years. It was the case of judicial officers of Delhi—increase in their salaries. What happened to that ? Two years ago, with the help of late Sanjay Gandhi I took up their case. From that moment, the Ministry of Home Affairs objected to it. I knew that they were not going to get it. Their first objection was that it is for the Law Ministry to do that. Okay. I went to the Law Ministry. The Law Minister was prepared to clear that provided the Finance Ministry cleared it. I followed that up like a chaprasi with the Finance. That Ministry said that they are prepared to accept it if the Law and Finance Ministries sit together. I

said 'Okay'. When I tried to get them back, they said that the file was in the Home Ministry. I went to the Home Ministry. They said that it was not with them. They had nothing to do with that. What happened ultimately was this. I tried to get the Law Ministry and the Finance Ministry to sit together with the help of our leaders. They formulated a thing. They said that the sessions judges of the courts should not be given the increased salaries. When the thing was cleared, they said that the file had to go to the Home Ministry. Initially, the Home Ministry said that they had nothing to do with it. All this took time. The bureaucrats sitting there were not going to allow this. I knew this. The Home Minister and our own leaders said that they wanted to help us. I knew in my heart of hearts that they will not clear it. Ultimately when I got the file cleared, the Home Minister sat with the Home Secretary and their officers concerned. They said it would be done. There was a nintynine per cent chance for it. There is only one per cent chance of this not being done. They had taken a decision already. Since the politicians have come to this House with the help of the people, their voice should not be heard. I say their voices should be heard. Who are these people to say that ? These are the very same people who showed disrespect to Mrs. Gandhi and who put her behind the bar. How are you going to expect them to implement the Prime Minister's 20-Point Programme ? Unless and until you move heavily on these people—when the Government changes, you should bring with you political secretaries in their places — it is not possible to assume that they will keep in mind the aspirations of these people of this country and will hear the voice of Mrs. Gandhi. Otherwise, who else are going to implement our policy ?

I strongly say this thing. Sir, even yesterday when one of our Hon. Member, Shri Tewary, spoke about the bureaucrats only one or two lines........

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI JAGDISH TYTLER : Sir, it is a very valid point. In China the bureaucrats were thrown on the roads and asked to go back to the villages as they had made mess of the whole thing. So, Sir, as I want the policies of my Prime Minister to get implemented and the policies of the Home Ministry to get implemented, I do not want bureaucrats to be involved in this because they are going to bring in all types of rules and regulations and then say such and such thing cannot be done. We have to face the electorate whereas they will be occupying their cosy seats. That is why I am making this point.

Sir, yesterday Mr. Tewary had spoken two lines criticising the bureaucrats. You know what happened. The T. V. and the radio did not mention his name. Today I am criticising the bureaucracy with an open mind because I am convinced let us see what happens. *(Interruptions)*

Sir, I would like to congratulate the Home Minister about liberalisation in pension. Those people deserved it. I want to congratulate him for that.

Sir, I would like to say a few words about the North Eastern State. These are the States which have been neglected. They want to come in the mainstream of the nation. There are certain things which they do not have, namely, steel, cement and other resources. They want to develop their industry. I would urgent upon the Government to pay attention to that side. We should provide them with better communication and transport facilities so that they can build up their basic structure and stand on their own legs and bet a part and parcel of our country. The North Eastern States have a vast treasure

[Sh. Jagdish Tytler]

house of natural resources. That should be developed. In that way we will create more jobs for them and raise their standard of living.

Last year also, Sir, I had mentioned about the police. Everybody criticises the police but how many times have we given them credit for the good work done by them. How many times have the Opposition and the Ruling Party come out with words of praise for the good work done by them. Sir, our population is rising and we have not even provided with bear requisites and expect them to do so many things. It is not possible. So I want to say that when they do a good job they should be commended. Apart from that children of most of the policemen live in the rural areas. They do not get proper schooling facilities. So, I would urge upon the Home Minister to provide housing and schooling facilities for them.

Further, Sir, they should be protected from the politicians who are interfering with their duties—the politicians may either belong to our party or the Opposition parties. Sir, when he is doing his duty no politician should be allowed to interfere with his work.

Sir, for the last three years I have been requesting that you should create a policemen welfare fund. I hope this year you will accept my plea and create a policemen welfare fund.

Lastly, Sir, there is a valley called Zanksar valley. I do no think anybody has been there. It is a small place situated on a glacier rock. I had the opportunity to visit that place. I had taken a team of doctors there. It is a place which is situated 18,000 ft. above; you have to cross three glaciers to reach there ; it is only open for 1-1/2 months in a year. I had gone there with a Member and we had taken a team of doctors with us. We went there. Sir, you should see the plight of these people there, how they have been neglected by the State Government. If today we say that Law and Order situation is a State subject and so on, the question is, who is going to protect these Buddhists in these Buddhist monastaries ? When we were coming down the mountains, we found hundreds of Lamas sitting on the road ; they have probably never seen people like us ; they said ; Please take our plight to Mrs. Gandhi ; we are being harassed ; those people across the mountains come and take our land ; they bring their cattle for grazing in these lands ; we have got only 1-1/2 months in a year to grow these grass; they bring their cattle for grazing; they bring their guns and they raid the monastaries. And, Sir, God knows what they do. I feel shy to say certain things, so many obscene things these people do. I would desire that when a thing like that happens, it should be the concern of the Home Ministry. Home Ministry is responsible even for those minorities who are in that particular region of the country. They are affected. They are harassed. They need your protection. They have one hope, that is, Mrs. Gandhi. If that hope breaks this country will break. Sir, one word more. People say, communal riots take place. This party blames that party; that party blames this party : we blame them ; they blame us ; now, my question is this : When you set up an enquiry when something has been pin-pointed when some forces have been identified, why don't you take action ? Why was not action taken against the people concerned in the Jamshedpur incidents ? What happened in Kanya Kumari when these incidents of communal riots were taking place: RSS people were there; why was not action taken against these people ? Some incidents took place here in our gallery. Before these people entered the House you should find out in whose house they collected before they came here. These people came and created a rumpus in the Parliament. Who are the people

who stood up, who reacted, who defended them? When these people were taken into custody in Parliament who were the people who went and supported them? Who ran away from the House straightway trying to defend these very people; they are doing exactly the same thing,— what they are doing out side. These RSS elements are the enemies of this nation and until and unless these communal elements are crushed you will not be able to solve this question I repeat what I said last year. Last year I pointed out to you about the specially sensitive areas. There are specially sensitive districts where communal riots take place. There are incidents of atrocities on harijans. There are areas where the disturbances take place because of the labour movements. What is happening? I saw in the report that you have very kindly instructed the State Ministry to look into these things. I would say: Make it a time-bound programme. You kindly tell them, please reply within a time-bound period; within a month's time or so. They should tell you what they have done, what steps they are taking to see that these communal riots do not take place. These are very important things.

Sir, one last point. Our country is a country of poor people. I make this request to our opposition people who are saying so many things. Our poor people are having the fullest trust and faith in Mrs. Gandhi. The opposition is trying to break this trust and this faith of these poor people. They are telling them things which are not true. I only request them: Please come up with any alternative thing which you have. That, they are not going. I do feel that you are not even worthy of the dust of Mrs. Gandhi's feet. I only request them not to break the people's trust and faith in Mrs. Gandhi because she is the sole person whose thinking is always for the poor people, who wants to do many things for the poor people and who is doing many things for them.

With these words I conclude. I support the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs.

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : सभापति महोदय, आपने जो मुझे गृह मंत्रालय की मांगों पर होने वाली डिबेट में बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज हमारे देश में असुरक्षा की भावना फैल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रजातन्त्र खतरे में है। अभी-अभी हमारे भाई इस बात की बड़ी चर्चा कर रहे थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में सारा देश सुरक्षित है लेकिन उनको इतने दिन राज करते हुए हो गए, आज आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि सारे देश में त्राहि-त्राहि मची हुई है, ऐसी स्थिति कभी भी देश में पैदा नहीं हुई थी। सभी राजनीतिक दल एवं समाज सुधारक लोग यही कहते हैं कि आज जैसी स्थिति देश में है, वैसी कभी भी नहीं थी।

आप उत्तर प्रदेश की ओर देखिए। कई और साथियों ने भी चर्चा की है लेकिन मैं विशेष तौर पर आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर बदले की भावना से, एन्काउन्टर के नाम पर सीधे-सादे लड़कों को मारा जा रहा है। डकैतों के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, प्रशासन और अनुशासन के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। लोगों ने तो यहां तक कहा है कि कोई आदमी जो कत्ल करता है उसको फांसी मिलती है लेकिन वह अपील में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और राष्ट्रपति महोदय से क्षमादान भी मांग सकता है लेकिन वह असहाय बच्चे, जिनको मारने वाली स्वयं सरकार है, वे कहां पर फरियाद

[श्री चन्द्रपाल सिंह]

कर सकते हैं? कहीं कोई सबूत नहीं और कोई कुछ कह नहीं सकता। आज इस प्रकार की जो असुरक्षा की भावना फैली है, कई लोग तो कहते हैं कि इस मामले को यू० एन० ओ० तक ले जायेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मानवता के नाते, इन्सानियत के नाते, न्याय के नाते, इस सम्बन्ध में आप कोई जांच करवायें ताकि आगे के लिए यह चर्चा न हो। आप इस बात को मत मान लीजिए कि विरोधी दल के लोग जो कुछ कहते हैं वह सही नहीं होता। क्या सत्ता पक्ष के लोगों ने ही सच्चाई का ठेका ले रखा है? कम से कम, यह जो एक चर्चा चली है और चारों तरफ एक भ्रांति फैली है, उसको दूर करने के लिए शासन का कर्तव्य है कि एक निष्पक्ष व्यक्त से, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से एन्काउन्टर्स के सम्बन्ध में जांच करवाए।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, यह सही है कि जहां पर आपके दल की सरकारें हैं वहां पर पुलिस से मिलकर विरोधी दल के लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप कम से कम इतना जरूर कीजिए कि पुलिस पर कोई पोलिटिकल दबाव या उसके काम में कोई दखलन्दाजी न की जाए। सारी जगह राजनीतिक लोग ऐसा करते हैं। मैं विरोध पक्ष को भी नहीं छोड़ता, मैं नहीं कहता कि जब वे शक्ति में थे तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभी राजनीतिक लोग अपने हितों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं।

आज पुलिस की जो दयनीय स्थिति है उसकी ओर भी आप निगाह जरूर डालें। एक गरीब सिपाही की तनख्वाह बहुत कम है। उसके लिए बच्चों की तालीम की व्यवस्था और मेडिकल फैसिलिटीज कोई नहीं हैं। उसको ऐसी सुविधायें मिलनी चाहिएं जिससे कि वह अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। वह 24 घंटे की ड्यूटी देता है लेकिन उसके रहने के लिए एक कोठरी होती है, वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। दूसरी ओर कोई सुविधायें उसको नहीं मिल रही हैं। इसकी तरफ भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

आज दुर्भाग्य से इस देश में अंग्रेजी का बोल बाला है। ज्ञानी जो स्वयं अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, उर्दू हिन्दी में ही बोलते हैं। अगर यही स्थिति रही और अंग्रेजी दां ब्यूरोक्रैसी का वजन बना रहा तो सारे देश पर उनका ही राज चलेगा और लोगों को न्याय नहीं मिल पायेगा। यह देश कभी ऊपर नहीं उठ पायेगा। जिस देश की तालीम और संस्कृति कमजोर होगी वह देश कभी ऊपर नहीं उठेगा। आज सैक्रेटेरियट और दूसरी जगहों पर अंग्रेजीदां लोगों की बात को बड़े वजन के साथ सुना जाता है। मेरी प्रार्थना यह है कि देश को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन वह दिमाग नहीं बदल रहा है, जब तक यह दिमाग नहीं बदलेगा, तब तक यह मुल्क नहीं उठ सकता है।

दूसरी बात मैं लाइसेंस के बारे में कहना चाहता हूं। कुछ लोगों को आप लाइसेंस देते हैं। उसमें कुछ गलत लोग हैं, जो पुलिस से मिलकर या राजनीतिक दबाव का फायदा उठाकर लाइसेंस ले लेते हैं। जो अच्छे आदमी हैं, वे रह जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सब के लिए फ्री कर दीजिए। शक्ति आपके हाथ में और पुलिस के हाथ में जब भी रहेगी और तब भी रहेगी। आज अगर गलत आदमी को नहीं रोक सकते हैं, तो बाद में भी नहीं रोक सकेंगे। इस लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हथियार लाइसेंस देने की

प्रणाली है, उसको तोड़ने की बात करें। सब को फ्री दर दीजिए, जिसको लेना है, वह ले और जिसको नहीं लेना है, वह न ले।

एक बात मैं हरिजनों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। जो भी हरिजन भाई यहां संदन में बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन डरते सब हैं। यह जो दिमाग बनाया जा रहा है कि सारे देश में हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो यह शोर मचा हुआ है और सारी दुनिया में आपकी पिक्चर जाती है कि आप हरिजनों पर दबाव डालते हैं, हरिजनों पर बड़ा भारी अन्याय करते हैं, ऐसा जो प्रचार हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। सरकार चाहे जो कोई भी हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार थी या आपकी सरकार है, सब लोगों ने उनके लिए पूरी कोशिश की और आज भी आप कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप नहीं कर रहे हैं। हरिजनों में कुछ दिमाग बनाया है कि समाज में अलग अपने आप को दिखा रहे हैं, जितना दबाव वे देते हैं। (व्यवधान)

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल सिंह : मेरा कहना आपसे यह है कि समाज में और लोग भी हैं—

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : आप समाज में बिगराव पैदा करने जा रहे हैं।

श्री चन्द्रपाल सिंह : मैं पेशावर नुमाइन्दे चार्ज लगाता हूं। मैं यह नहीं कहता कि उनको ऊपर नहीं उठना चाहिए, वे भी समाज के अंग हैं, उनको भी ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सरकार के ऊपर निर्भर रह कर और यह दिमाग बनायें कि देश में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो यह देश की ख्याति के अनुरूप नहीं है। समाज में और भी लोग हैं, उनकी ओर भी घ्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : यदि कोई दूसरा प्वाइंट है, तो उसके बाद में कहिए।

श्री चन्द्रपाल सिंह : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

SHRI MAHENDRA PRASAD (Jahanabad) ; Mr. Chairman Sir, a peep into some distant past, the last month and perhaps many more months of the year 1979 and the subsequent year, when the Assam problem came on the surface and the incidence of Afghanistan at a stone's throw distance from our motherland became visible and when the devouring, gnawing teeth of Khalistan started showing its ferocity with a dozen clashing, cutting each other's throat, personalities aspiring for Prime Ministership, a worried patriot is reminded of and rejuvenated with the famous couplet of Iqbal :

ईरान मिस्र रुमा सब मिट गए जहां से।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी॥

Sir, a heart with patriotic feeling starts sinking when one imagines what would have happened to the country, if the auspicious happenings

[Sh. Mohendra Pd.]

of those first and second weeks of January 1980 would not have come to the rescue of the nation. The country would have been cut into pieces and ruined. I am afraid even slavery might have be fallen, to free from the yoke of which lots of sacrifices have been made in the not too distant past by our great leaders and people. Here comes the wisdom and carefully—assessed judgement of India and its people by Iqbal. One derives comfort and solace from those famous couplets of that great poet, Iqbal. India and its people are great. The sacred soil of India has great capacity. India emerges out of ruin. Our wisdom prevails over our failings and failures. We overcome our weaknesses and become stronger. We learn from our mistakes. We falter, fall and rise again. We are imperishable; we are immortal.

Sir, some of our previous big guns and small speakers from the other side of the House have pointed out that there is a chaotic atmosphere in the country. They say there is no law and order; there are riots; there are dacoities, robberies and thefts; there are murders, rapes and all sorts of crimes; there is price rise, inflation and unemployment; there is no Government. They say that the present Government is full of vices, with no virtue, and that all good things that a Government does, have ceased in the first fortnight of 1980, when the present Government took over. We deny it, and have proved it factually. A number of times, our Ministers and speakers from our side have proved with facts and figures that what our friends say about us is baseless. Our performance is superb, especially when we compare ourselves with theirs, and they know it within their hearts, ihspite of their assertion and outbursts to the countrary.

However, there are problems in the country; and they are numberless. We have to solve them without any loss of time, if we have to survive. We have problems—social, political, economic. We have our enemies on our borders, aspiring to swallow us at the first opportunity. We had problems at Moradabad and many other problems like this. But how to solve these Problems ? If we have to solve these problems, the Government will have to go very very strong and tough ; we will have to pursue a ruthless policy in the national interest. But the moment the Government shows its grain and becomes tough, immediately come the cries from the opposition that democracy is in danger. Everyone knows the fate of Emergency. Sir, non-understanding of democracy and all the hullaballoo and loose talk about democracy is causing great harm to the society and the country. People talk of democracy without knowing what democracy is.

Sir, what is democracy? Democracy is a situation, or a system or a state of affairs where everyone expresses his or her opinion, in his or her self-interest. In absolute terms, expression of opinion in self-interest is the name and meaning of democracy. Any other interpretation of democracy is opportunistic, adulterated and wrong; such interpretations are altering the meaning to suit one's convenience. The essence of democracy is equality. In demo cracy, everyone has to be compulsorily equal to know his or her self-interest. To know his or her interest equally, everyone has to compulsorily have equality of knowledge and mental and intellectual equipment. Therefore, equality of knowledge and mental and intellectual equipment among all, without exception, is a pre-requisite for democracy. One knows one's self-interest through knowledge and ability. Therefore, equality of knowledge and ability among all is essential. But how can the equality of knowledge and ability be achieved ? Many factors contribute to the building and achievement of knowledge or ability.

Therefore, availability of these factors equally to one and all is necessary. One very important factor that most dominantly contributes to achievement of knowledge and ability is money. A moneyed person or the children of such person, if not spoiled, through acquisition by money power of factors that contribute to knowledge and ability, will be more knowledgeable than a poor person or the children of such person who cannot afford to purchase facilities that enhance knowledge and ability. A mill-owner's son will be more informed and knowledgeable than a rickshaw-puller's son. To the extent there is disparity in purchasing-power among the people, there will be disparity of knowledge among the people to the same proportion. Absolute parity of income is most essential. Therefore, an ideal, and only, society for achieving democracy is one where work is given according to ability and remuneration according to need without any deviation whatsoever. Such a society is non-existent in the world. And now, Sir, even if this difficult task of establishing a world society with complete and absolute economic parity is achieved, the question is whether, inspite of achieving parity of income among all, it is possible to have parity of knowledge and ability among all people which is so essential to realize the goal of absolute democracy? To remember here is the thing that money is not the only factor that contributes to acquisition of knowledge or ability. There are other factors also and many of these factors are not within control of human competence as per the so far developed science and technology.. As for example geographical and biological factors also contribute to human competence and knowledge. A person of particular region like mountains may not have the same competence as that of region like planes and sea-shore or vice-versa. It differs from place to place and country to country—a warm country's peoples competence and efficiency may differ from that of a cold country's people. Then, competence also differs according to biological possession of an individual it also differs according to sex. Therefore, Sir, human competence, knowledge and abilitywise, is bound to difffer from person to person as a consequence of which knowledge of 'self-interest' is bound to differ from person to person and as such expression of correct opinion to serve self-interest will suffer and as a result of all this realization of democracy will not be achieved.

In my very carefully and thoughtfully considered opinion, correct democracy is an ideal never to be achieved and there is no democracy in the world, neither in the U.S.A. nor in the U.S.S.R. nor anywhere in the world. Democracy is a mirage ; let us not waste our energy for an illusion.

Let us have a look at the history of prevalent democracy, not the democracy which I talked above. How has it developed from monarchy to its present state ? The present day democracy is a result of clash of interests ; in it the rule has delegated from one to many; it is not the rule of all, one has been dethroned by many but many have not been dethroned by all. The present day democracy is an outcome of opportunistic tendency. The U.S.A. and the U.S.S.R. both with different and conflicting ideologies and social order claim to be the champion of democracy. Is it not strange ? However, I agree the prevalent democracy is not a bad, rather a good, working hypothesis. Let us continue with this; let us honour this ; let us work with this till a better alternative is achieved. But let us remember the taste of any philosophy is the good that it does to the society.

[Sh. Mohendra Pd.]

Democracy should not be used as a dogma; it must be discarded and we must free ourselves from the fetters of it if it comes in the way of national interest. Democracy should not mar the progress of our people; it should not jeopardize national interest.

We have many problems. We need to act strongly. The cries for democracy should not come in the way. Let us serve the people. The good of the people is supreme, not democracy. Democracy is for the people; and not the people for democracy. I support the demands.

AN HON. MEMBER : An excellent speech !

MR. CHAIRMAN : Shri Uma Kant Mishra.

श्री उमाकांत मिश्रा (मिर्जापुर) : माननीय सभापति जी, मैं गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की, उसको विकसित किया, आगे बढ़ाया और आज भी जो लोकतंत्र को चला रहे हैं, उनका हर काम प्रतिपक्ष को लोकतंत्र विरोधी नजर आता है।

श्रीमन्, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना का नेतृत्व पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था और स्वतंत्रता की लड़ाई के समय से ही उन्होंने इस देश के लिए संसदीय लोकतंत्र का ढांचा बनाया था, कल्पना की थी और स्वतंत्रता के बाद उनके नेतृत्व में संविधान बना और संसदीय लोकतंत्र को उन्होंने सफलतापूर्वक मजबूत बनाया। उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाया और लोकतंत्र के जरिए इस देश को दुनिया में शानदार स्थान दिलाया, विकसित किया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी का हर काम, इनके दल का हर काम प्रतिपक्ष के लोगों को अलोकतंत्रीय नजर आता है। यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है और इनकी पार्टी द्वारा शासित प्रदेशों में किया जाने वाला हर अलोकतंत्रीय कार्य इनको लोकतंत्रीय नजर आता है। इस प्रकार इनका लोकतंत्र का ढोंग, नाटक जनता की समझ में नहीं आता।

मैं बहुत विस्तार में न जा कर केवल इतना ही कहूंगा, एक बार कारलाइल ने कहा था "इट इज ए टाकिंग शाप।" मगर हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने पार्लियामेंट को शार्उटिंग शाप समझा है और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है।

जब केरल में नयनार की सरकार थी तब लोकतंत्र खतरे में, जब करुणाकरण की सरकार थी, तब लोकतंत्र खतरे में, असेंबली डिजाल्व हो गई तब लोकतंत्र खतरे में है, जब यहां जमाखोरी के खिलाफ कानून पेश हुआ तब लोकतंत्र खतरे में, आवश्यक सेवाओं के अनुपालन के लिए विधेयक आया तब लोकतंत्र खतरे में, हर कदम पर लोकतंत्र खतरे में, यह बात हमारी समझ में नहीं आती।

महोदय, पार्लियामेंट एक महत्वपूर्ण सभा है, यहां प्रतिपक्ष के लोगों को भी सोच-समझ कर बात कहनी चाहिए। हर जगह इनको लोकतंत्र खतरे में नजर आता है।

अगर प्रतिपक्षी दलों की विवेचना की जाए, देखा जाए और इनको संविधान बनाने का मौका दिया जाए तो आप देखेंगे कि ये लोकतांत्रिक संविधान नहीं बनाएंगे।

मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि इनका कभी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रहा। ये तो डिक्टेटरशिप में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ लोकतंत्र को तोड़ने के लिए। जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, केरल में हो रहा है, वहां संसदीय लोकतंत्र का इस्तेमाल लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है।

आप कैसे लोकतंत्र को मान सकते हैं। यदि संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो आप कार्ल मार्क्स में विश्वास नहीं रखते। इनका क्या लेनिन में विश्वास नहीं है, माओ में विश्वास नहीं है और इनको अगर संविधान बनाने का मौका दिया जाए तो क्या ये ऐसा नहीं बनाएंगे जिस में वन पार्टी रूल की व्यवस्था हो जैसे रूस में है, चीन में है या कास्त्रो ने कर रखा है। लोकतंत्र की दुहाई ये क्यों देते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। वाजपेयी जी को संविधान बनाने का मौका दे दिया जाए तो क्या गुरु गोलवलकर या देवरस साहब या आर. एस. एस. की भावना से मुक्त होकर ये संविधान बनाएंगे? कैसा संविधान ये सब बनाएंगे इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह को अगर संविधान बनाने का मौका दे दिया जाए तो उस संविधान की पहली धारा होगी कि आजीवन चौधरी साहब देश के राष्ट्राध्यक्ष होंगे और सारी सत्ता उनमें निहित होगी। सारा समय यह नारा देने में ही खर्च कर देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। यह कहते रहने के बजाय जनहित की बात क्यों नहीं करते हैं, जनहित में जो चीजें हैं उनको डिसकस क्यों नहीं करते हैं, उन पर वाद विवाद क्यों नहीं करते हैं। संसदीय लोकतंत्र का महत्व इसी में है कि समस्याओं पर — वाद विवाद किया जाए, विचार विमर्श किया जाए, जनहित के प्रश्नों पर विचार किया जाए, अपनी राय दी जाए ताकि देश को और जनता को लाभ हो।

ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि इस धरती पर चोरी, डकैती, कत्ल, अपराध सब समाप्त कर दिए जाएंगे, बिल्कुल भी ये नहीं होंगे। न इतिहास में ऐसा कभी हुआ है और न होगा। अपराध होते हैं, चोरियां होती हैं, डकैतियां पड़ती हैं। विपक्ष के लोग यह कहें कि धरती पर स्वर्ग आ जाए तो यह सम्भव प्रतीत नहीं होता है। देखना हमें यह होगा कि सरकार अपराधों को रोकने के लिए, शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है, दत्त चित्त हो कर इस काम में लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, प्रभावकारी कदम इस दिशा में उठा रही है या नहीं उठा रही है। निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि हमारी सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, ज्ञानी जैल सिंह के नेतृत्व में इस देश में शान्ति व्यवस्था की स्थापना के लिए, साम्प्रदायिक सद्भावना की स्थापना के लिए, राष्ट्रीय अखंडता और एकता की स्थापना के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। हमारा विशाल देश है, हमारे देश की विशाल जन संख्या है, विभिन्न भाषा भाषी लोग यहां बसते हैं, विभिन्न धर्मावलम्बी लोग इस देश में रहते हैं। ऐसे देश में शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्रयास हो रहा है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। यहां पर सारे देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की बहुत आलोचना की

[श्री उमाकान्त मिश्र]

गई हैं। 1980 में जब से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार चुन कर आई थी इस देश के असामाजिक तत्वों ने, कुछ सियासी ताकतों ने भी यह कोशिश की कि उतर प्रदेश की सरकार फेल हो जाए। मुरादाबाद में दंगे भड़काए गए, अलीगढ़ में दंगे भड़काए गए, अपराधियों को उकसाया गया लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के नेता और विशेष कर वहां के मुख्य मंत्री विश्व नाथ प्रताप सिंह जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ स्थिति का मुकाबला किया, साम्प्रदायिक एकता की स्थापना की और उसका नतीजा यह है कि आज साम्प्रदायिक दंगों में वहां कमी आई है। यह कहा जा रहा है कि अपराध बढ़े हैं, शान्ति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। लेकिन आंकड़े इसके विपरीत हैं। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हम देख रहे हैं कि वहां डकैतियों में कमी आई है, साम्प्रदायिक दंगों में कमी आई है, अपराधों की प्रवृति में कमी आई है। उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां के मुख्य मन्त्री ने दृढ़ता के साथ डकैत उन्मूलन आप्रेशन चलाया है और अपनी इस दृढ़ता का मूल्य उनको चुकाना पड़ा है, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। हाल ही में उनके बड़े भाई जस्टिस सी० एस० पी० सिंह की हत्या कर दी गई, उनके भतीजे की हत्या कर दी गई। यह बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। मेरा विश्वास है कि उनके भाई का खून जरूर रंग लाएगा। महाबीरा का गैंग जो बहुत मशहूर गैंग था और छवि राम के गैंग को खत्म कर दिया गया है। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता हूं लेकिन भूरा गैंग, रघुनाथ सिंह गैंग, पपुआ गैंग, सुरेश सोनी गैंग, राधे संतोषा गैंग, मुन्ना डाबर गैंग, भीमा मल्लाह गैंग, रघुनाथ मल्लाह गैंग आदि का सफाया कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में हरिजनों, आदिवासियों, बैकवर्ड क्लासिस और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहां एक डी० आई० जी० इनके लिए अलग से है। एक सैल भी वहां इनके लिए बनाया गया है जहां इनके कैसिस की सुनवाई होती है, जो इनके कैसिस को देखता है। प्रत्येक जिले में अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि हरिजनों और आदिवासियों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं, इन पर जो अत्याचार होते हैं, उनकी वे स्वयं जांच करें। ये जो सब कदम उठाए गए हैं ये बहुत प्रसंशनीय हैं और इन से उनकी भलाई के कामों में बहुत योगदान मिला है जो कि प्रशंसनीय है। इसलिए यह कहना कि उतर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था खतरे में है, सर्वथा गलत है।

14 hrs.

अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है। अगर देश और प्रदेशों में शांति व्यवस्था बनाये रखना है, अपराधों का उन्मूलन करना है, शांतमय तरीके से औद्योगिक और कृषि विकास करना है, लोगों की जानमाल की रक्षा करना है तो यह जरूरी है कि पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाय। पुलिस को आप को आधुनिक हथियार देने पड़ेंगे, उनको वैज्ञानिक तरीके की शिक्षा देनी होगी, पुलिस कर्मियों के रहने के लिये निवास स्थान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तो यह करना और भी जरूरी है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अन्य जो विकास के बजट हैं, क्योंकि राज्य, शासन और सरकार का बुनियादी कर्त्तव्य है देश की रक्षा करना,

जनता की जानमाल की रक्षा करना, अतः जानमाल की रक्षा करने के लिए अगर अन्य प्रकार के बजटों में कुछ कटौती भी की जाय तो वह क्षम्य है। जब डाकुओं के हाथ में स्टेन गन हो, कारबाइन हो और 10 पुलिस वाले साधारण बन्दूक ले कर घूम रहे हों तो वह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते, जनता की क्या रक्षा करेंगे ? ऐसी स्थिति में पुलिस को अधिक शक्तिशाली बनाना होगा और आधुनिक हथियार तथा वैज्ञानिक ट्रेनिंग उनको देनी ही होगी तभी शांति व्यवस्था में सुधार होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूँ।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : Mr. Chairman, if we are honest, we must admit that things are not well anywhere. There is practically crime everywhere, and crime cuts across party lines. And any cry against crime is a cry in wilderness. There is crime against minority communities, against workers, against the weak and exploited within the country. What is more disturbing is that there is something basically worng in the system, in the Government, specially in the Home Ministry.

There is devaluation of not only other things but also values of life. We are not surprised to hear or see any ugly things in the country. We have become reconciled to anything. Some Hon. Members are complaining that there is thin attendance in the House. There is thin attendance perhaps in other areas also. It means that we have become reconciled to this fate. We have developed some sort of fatalism that whatever we may say, whatever we may ask, nothing is going to happen, there would be no change.

Whenever we raise the question of law and order, we are told by the Chair that it comes in the State sector, land belongs to the State sector, coal belongs to the Central sector and so on. I would like to know to which sector life belongs. When life is in danger, when honour is in danger, when the future is in danger, in which sector will it fall ? Will it be in the State List, Central List or the Concurrent List ? (*Interruptions*) I accept it, it may be a new sector.

Our Home Ministers, whenever they go outside their sphere, suddenly all the wisdom starts dawning on them. Some time back the then Minister of State for Home Affairs went to a State, which is not controlled by their party, and then started making observations that the law and order situation in that State is not good.

I would like to read certain observations made in *The Statesman* dated 25th September 1981, on the statement of the Ex-Minister of State for Home Affairs. It is stated :

"Mr. Yogendra Makwana's saying that political murders take place in "Communist run" States is irresponsible enough to imply that one kind of murder is more reprehensible than others.......Delhi is the worst offender in this respect. 31 murders were committed in the Capital between January 1 and August 15 this year against 28 in the whole of 1980. In the last year with 644 crimes for every 100,000 persons the Union Territory topped the country's crime list according to the survey conducted by the Centre.......... Number of recorded communal clashes increased from 188 in 1977 to 427 in 1980."

This is the picture.

[Sh. A. K. Roy]

Another point is that even in today's papers you will find what is happening in Uttar Pradesh. They are all talking of Uttar Pradesh. There, in Unnav district, in Rallis India Ltd. there was firing by the police. Sir, you are also intetested in the labour movement and you will be surprised to know that according to the officail records, till today 20 persons are missing and I can give you the names of the persons killed. This is most disturbing. Now, everything but human life is accountable. There is nothing to account for human life. I can give you an illustration of this. There was police firing in the first week of January, i.e., 3rd January, when the workers were on sit-in-strike in Rallis India Ltd. owned by Tatas. On the last occasion this Ministry gave us an assurance that the Essential Services Maintenance Act would not be used against the workers, but they used it here. And I was told that at the instigation of the Centre, that is, the Home Ministry, the Essential Services Maintenance Act was used because that factory was owned by one of the biggest monopolists of the country, Tatas, And, Sir, the police fired 50 to 60 rounds. Within the factory they fired and the workers were dragged and beaten to death. After that they followed the workers to their houses in the Harijan village and in that village called Dayal Khera, the Harijans were assaulted and beaten brutally and a large number of people are missing. I can give you the names of the persons who are not found there till today and the entire areas was restricted and all the outsiders were forbidden to enter into the entire area. This has also appeared in all the papers. It came in *Blitz* first, then in came in *The Patriot* today, it also came in *Indian Express*, and it has now become a serious thing that persons are still missing. They are not accounted as to whether they are dead or alive. The names of persons missing are : Ram Naresh Tripathi, Subedar Singh, Maneswar Singh, Ali Qamar, Ramzan Ali, Akbar Ali, Rafiq, Puthu Lal, Pyare Lal, Ram Naresh Verma and Chandradeo. They are all permanent workers who are still missing. This is the situation there.

Now, I would like to tell two or three things about our constituency. You know, Sir, that many tribal people are in the coalmines and you will be surprised to know - this is what I want to bring to the notice of the Home Ministry—that in the last 5 years not less than 5000 tribal workers were removed from the rolls showing them resigned or showing them that they have voluntarily abandoned their jobs. It is a very serious thing. It is not so small a number that we can take it up with the Labour Department. The Home Ministry should institute an inquiry to see how such a large number of tribal people are shown suddenly as resigned or having left their jobs.

Lastly, I would like to tell the Home Ministry that every case of encounter must be probed by the Central Ministry. Every case of killing of Harijans and Tribals and such criminal cases must be pursued by the Home Ministry so that the guilty are punished properly. Communal riot has nothing to do with the State sector. In all such communal riots national interests are involved.

Lastly, I would like to conclude by saying that the basic crisis or the defenct in the system is that the element of justice is gradually getting withered away from the entire body politic, and I would like to remind the Home Ministry that law and order is not the end, it is the means. End is justice. Where justice is denied, disorder is the sign of life. History has proved that many rulers tried to do many things with bayonet, but nobody could sit on it and this Government which is going to sit on it will meet the same fate which similar others met in history.

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाबे आली, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका बख्शा है कि मैं भी इस डिबेट में हिस्सा ले सकूं। मेरा मकसद कोई लम्बी तकरीर करने का नहीं है। कुछ बातें यहां पर कही गई हैं, जिनका मैं जवाब देना चाहता हूं।

मैंने हमेशा अपील की है अपनी पार्टी से भी और दूसरी पार्टियों से भी कि जब तक नेशनल प्राब्लम्ज को नेशनल तौर पर डील न किया जाए, उन्हें नेशनल तौर पर स्टडी न किया जाए और उनके बारे में कोई नेशनल कानसेनसस न हो, तब तक उनका हल ढूंढना बहुत मुश्किल हैं। अगर यह सब कुछ किया जाए, तब भी यह यकीनी नहीं है कि हम उन प्राबलम्ज का कोई सेटिसफेक्शन जेनीरेटिंग हल ढूंढ सकेंगे या नहीं। लेकिन उससे यह फायदा जरूर होगा कि सब पार्टियां नेकनीयती से कहेंगी कि ये मुश्किलात हैं और इनके बारे में जो कुछ मुमकिन हो सकता है, वह हम कर रहे हैं।

जब भी हमारे देश पर कोई बड़ी भारी विपदा आई, तो सब ने इकट्ठे होकर उसका मुकाबला किया। मुझे याद है—मेरी आंखों के सामने वह नक्शा है कि बंगला देश की जंग के वक्त किस तरह से सब पार्टियों ने इकट्ठे होकर तकरीरें कीं, इस देश को जगाया और एक होकर उस खतरे का मुकाबला किया। उससे पहले ही हमारे मुल्क पर एक बड़ी भारी विपदा आई थी। उस का मुकाबला करते-करते बंगला देश के साथ हमारी जो चक्कलश हुई, वह लाजमी थी। अगर वह न होती, तो हम फिनांशल तौर पर और भी तबाह हो जाते। उस वक्त हमारे जवानों, देशवासियों और नेताओं ने जिस बहादुरी और एकता का सुबूत दिया, वह किसी से छिपा नहीं है।

इस बात को सामने रख कर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज जिन दिक्कतों और मुसीबतों से सारा मुल्क दो-चार हो रहा है, अगर हम उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो खराबी और भी बढ़ेगी। लोगों को तसल्ली देने के लिए यह जरूरी है कि हम यह कह सकें कि जहां तक हम पहुंच सकते हैं, वहां तक पहुंच गए हैं और जो कुछ भी हम कर सकते हैं, वह हम कर रहे हैं।

जहां तक होम मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि सेंटर की होम मिनिस्ट्री की पोजीशन कांस्टीट्यूशनली बड़ी आर्टीफिशल सी है। ला एण्ड आर्डर एक स्टेट सब्जैक्ट है, यह सही बात है। अगर किसी जगह पर ला एण्ड आर्डर में खराबी हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं तो यहां पर भी लोग शोर मचाते हैं, वह भी सही बात है।

यहां बात भी न करें तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि फिर आवाज कहां उठेगी? लेकिन मुझे अपोजिशन से गिला इस बात का है कि ये डबल स्टैण्डर्ड रखते हैं। जिन सूबों में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमैन्ट्स हैं वहां की ला एण्ड आर्डर सिच्युयेशन पर तो ये यहां पर बहुत शोर मचाते हैं, जिसका हमें जवाब भी देना पड़ता है लेकिन जिन सूबों में कांग्रेसी गवर्नमैन्ट्स नहीं हैं वहां की बात अगर वहां पर उठाई जाए तो उसके लिए कहते हैं कि यहां पर यह सवाल नहीं उठा सकते और उसके लिए शोर मचाते हैं। इसलिए किसी भी चीज का एक ही स्टैण्डर्ड होना चाहिए। हमारे सी॰ पी॰ एम॰ या

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

किसी दूसरी पार्टी के लोग यहां पर यू० पी० के बारे में तो नुक्ता-चीनी कर सकते हैं लेकिन अगर यहां पर बंगाल की नुक्ता-चीनी हो तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको बंगाल की नुक्ता-चीनी भी सुन लेनी चाहिए और उसीके हिसाब से अमल करना चाहिए।

सभापति जी, आप सुन कर हैरान होंगे, मैंने एक दिन तीन आदमियों को जिनमें दो बंगाल के थे और एक अमृतसर का था, उनको विजिटर्स गैलरी के पास लेकर दिए और उन तीनों ने आकर यहां लोक सभा का जीरो आवर देखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको देख कर शर्म आई, क्या यही लोकसभा है ? हमें अफसोस है कि हम यहां देखने के लिए क्यों आए। जब यहां पर ऐसा आदर्श रखा जायेगा उसके बाद ला एण्ड आर्डर कैसे रह सकता है ? जब कोई नौजवान यहां से देख कर जायेगा तो वह क्या कहेगा ? उस अमृतसर वाले आदमी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं चाहूँगा कि मेरी आगे की नस्ल भी कभी यहां देखने के लिए न आए। मैंने उससे कह दिया कि लोक सभा के साथ राज्य सभा को भी जोड़ दो क्योंकि वहां भी तो ऐसा ही होता है।

मैं यह कह रहा था कि हमारा एक ही स्टैण्डर्ड होना चाहिए। हमारे स्पीकर, डिफरेन्ट लीडर्स के साथ बात-चीत करके जो यहां पर प्रोग्राम रखते हैं उसको मानना चाहिए। कोई भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वह कांग्रेस का हो या अपोजीशन पार्टी का हो, कभी नहीं चाहता कि डायरेक्टली इन्डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री उसके काम में मदाखलत करे। कोई भी इसको पसन्द नहीं करेगा। न तो ये उनके खिलाफ पर पूरा जवाब दे सकते हैं और न डायरेक्टली सी०बी०आई० वहां जा सकती है। इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। इसको अगर आप छेड़ते हैं तो सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करेंगे और लोगों को यही बतलायेंगे कि जमहूरियत का जो तरीकेकार है वह बेअसर है, पागलों की तरह से लोग यहां पर शोर मचाते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। इसलिए जो लोग लोकतन्त्र को चलाना चाहते हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि वे इस तरीकेकार को बदलें।

यहां पर नीरेन घोष साहब ने यह फरमाया कि फारेन अफेयर्स, डिफेन्स और कम्युनिकेशन—इन मोहकमों को ही सेन्टर में रखना चाहिए और बाकी राज्यों को दे देना चाहिए। 1935 का जब ऐक्ट बना था उस वक्त के राजे-महाराजों और नवाबों ने वही डिमाण्ड रखी थी जिसको कि आज हमारे बंगाल के दोस्त रख रहे हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में जो लोग कांस्टीट्एन्ट असेम्बली के लिए चुने गए थे और जिन्होंने कांस्टीट्यूशन बनाया था उसमें बड़े नालिजिएबल थे, पैट्रियाट्स थे, हाई क्लास के वकील और जज थे, जिन्होंने कि इस मुल्क के लिए कुर्बानियां की थीं। उन लोगों ने बहुत सोच-विचार के बाद आईन तैयार किया था।

सैन्टर के पास जो पावर है, वह कौन इस्तेमाल करता है, वे इस्तेमाल स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। यदि उन्होंने आर्टिकल 256 और 257 देख लिया होता तो उसमें सिर्फ सैन्टर को यह हक है कि वह अपने काम के लिए स्टेट को डायरैक्शन जारी करती हैं। वे महकमें जो डायरेक्टली फंक्शन कर रहे हैं, उनको छोड़ कर बाकी काम स्टेट के जरिए करवाते हैं। वरना क्या होगा यदि हम इनकी बात मानेंगे तो

बैकवर्ड एरियाज़ बैकवर्ड रहेंगे और फारवर्ड एरियाज़ और भी फारवर्ड हो जायेंगे। आप यह समझते हैं कि इन्डस्ट्री को हम स्टेट सबजेक्ट बना दें और यहां पर सिर्फ तीन-चार स्टेट्स ही बढ़ती रहेंगी और हम हमेशा के लिए गुलाम रहेंगे। यदि तीन-चार मेंहकमे ही केन्द्र के पास रह गये तो आप क्या प्लानिंग करेंगे। मुल्की पैमाने पर प्लानिंग नहीं होगी। गरीब स्टेटस क्या प्लान करेंगी। हिमाचल क्या प्लान करेगा, जे एंड के क्या प्लान करेगा। छोटा पंजाब या हरियाणा क्या अपनी-अपनी प्लानिंग करेंगे। इस प्रकार इस मुल्क के टुकड़े हो जायेंगे और आप उसको रोक नहीं सकेंगे और हम अमीर स्टेटस के गुलाम रहेंगे।

आपका शिपिंग और ट्रांसपोर्ट विभाग है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट और सड़कें आती हैं तथा हाई-वेज़ आते हैं। यह सब कुछ अगर छोड़ दें तो इसका मतलब है कि पहाड़ी दुर-दराज के इलाके बिल्कुल कट-आफ रह जायेंगे। चन्द एक जो कोस्टल स्टेट्स हैं, वे ही सिर्फ जहाजरानी का फायदा उठायेंगे और बाकी मुल्क को इसका फायदा नहीं होगा। रैजिड्यूरी पावर्स हैं वे केन्द्र में रहनी जरूरी हैं। इस किस्म की डिमांड राजा-महाराजाओं ने और नवाबों ने की थी, पावर्स को अपने पास रखने के लिए और लोगों को गुलाम बनाने के लिए। आपने यह भी देखा कि आज हमारे इर्दगिर्द क्या हो रहा है। बंगला देश में एक नई खबर आई है। वहां फिर कूप हो गया, मिलिट्री कूप होने के बाद आर्मी ने टेक-ओवर कर लिया है। हमारे दायें-बायें इस तरह की बातें होती रहें। इससे हमारे मुल्क को खतरा पैदा होता है यदि इस बारे में हमें एक एप्रोच न बनायें, तो हम खतरे से बच नहीं सकते। झगड़ों की तरफ आप इशारा करते है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक आप प्रोडक्शन आफ वैल्थ और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक तरीका नहीं निकालेंगे तो ये बातें होती रहेंगी। श्री चन्द्रजीत यादव जी ने बहुत सारी बातें कहीं, जो अच्छी बातें हैं, हमें उन की कदर करनी चाहिए। उन्होंने फ्यूडलिज्म की बात कहीं और कहा कि यह नए फार्म में आ रही है। तमाम एग्रीकल्चर को मैकेलाइज कर दिया है। बहुत से लोग बेकार हो गये हैं। गरीब काम करना चाहता है, काम करके खाना चाहता है। यदि काम न मिले, मांगेगा, मगर मांगने पर भी खाना न मिले तो वह लूटेगा। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मेरे पास जमीन नहीं है। हमारे यहां लैण्ड रिफार्म हुआ है, हमने जमीन दी शायद और भी जायेगी। हर इन्सान को जीने का हक है। दुनिया में इन्सान नंगा पैदा होता है और हर इन्सान के लिए जमीन बनी है। अगर मीन्स आफ प्रोडक्शन को काबू करके लोगों को गुलाम बना कर रखेंगे तो फसाद होंगे, डांके पड़ेंगे, चोरियां होंगी। लैंड रिफार्मस पर और जोर देने के लिए होम मिनिस्ट्री को कोशिश करनी चाहिए। और भी बहुत सी बातें हैं, जिन पर उनको ध्यान देना चाहिए। बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, जो ना उम्मीद हो चुके हैं कि उनको काम नहीं मिलता है। उनके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, बेकारों, भूखों की ला एण्ड आर्डर से दुश्मनी है।

जब हम उस मसला पर नहीं सोचते हैं, तो हमारा नौजवान खासकर पढ़ा-लिखा नौजवान है, एक ऐसा रास्ता अख्तियार करता है, जो गलत है। वह तोड़फोड़ की

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

तरफ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए।

होम मिनिस्ट्री ने ट्राइबल्स के लिए बहुत कुछ किया है और उन को आगे बढ़ना भी चाहिए, शैड्यूल्ड कास्ट्स को आगे बढ़ना चाहिए और अगर आप बजट को देखेंगे तो कम्पैरेटिवली वह बढ़ रहा है और प्लान में उनके लिए ज्यादा पैसा रखा गया है। इस तरह से होम मिनिस्ट्री जो कुछ कर सकती है, वह कर रही है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो फंडामैन्टलइज्म की बात है, इस की मुखालफत होनी चाहिए चाहे वह हिन्दू फंडामैन्टलाइज्म हो, चाहे मुस्लिम फंडामैन्टलाइज्म हो और चाहे सिख फंडामैन्टलइज्म हो। कभी खालिस्तान का नाम लिया जाता है तो कभी किसी और का नाम लिया जाता है। फंडामैन्टलइज्म की हम मुखालफत करें और उस को आगे न बढ़ने दें। अभी अनन्तनाग में जो एक शोर मचा था, वह भी मुस्लिम फंडामैन्टलइज्म की वजह से था, चन्द कट्टर लोगों ने आकर गड़बड़ की। ऐसे चन्द आदमी ही हैं और हर जगह ऐसे ज्यादा आदमी नहीं होते हैं। वे ही फसाद करते हैं और फिर कहते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम फसाद हुआ है। आपस में झगड़ा हो गया, तो ला एण्ड आर्डर की बात कही जाती है और गरीब आदमियों को लूटते हैं, तो कोई बोलता नहीं है।

एक और बात कहना चाहता हूं। यहां पर कुछ लोग गृह मन्त्री की नुक्ताचीनी करते और मजाक उड़ाते हैं। होम मिनिस्ट्री में जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, लश्कर सहाब को बहुत नीचवाद हैं, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने जमाने में कितनी कुर्बानी की है लेकिन ज्ञानी जी और वेंकटसुब्बयया जी के बारे में मैं जानता हूँ। जब ज्ञानी जी की नुकताचीनी करने वालों को मैं देखता हूं, और ज्ञानी जी को देखता हूं, तो यह कह सकता हूँ कि जिस वक्त उनमें से कुछ लोग घुटनों के बल चलते थे, उस वक्त ज्ञानी जी जेल में सड़ रहे थे और ब्रिटिश इम्पीरियलइज्म से लड़ रहे थे। वे ब्रिटिशर्स की जेल में नहीं थे बल्कि स्टेट की जेल में थे और उनकी हालत क्या थी, इसके बारे में पण्डित जी ने लिखा है कि किस तरह की तकलीफें वहां थीं और किस तरह से यह कोशिश की जाती थी कि इन लोगों को खत्म किया जाए। हमारे ज्ञानी जी पढ़े-लिखे आदमी हैं। यह और बात है कि वे अंग्रेजी कम जानते हैं मगर तालीम में वे किसी से कम नहीं हैं। वे चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उस वक्त उन्होंने फिरकापरस्ती की जो हवा थी, उस को तरीके से रोका। यह बात हमको याद रखनी चाहिए।

एक बात और कह दूं कि सिखों के दस गुरु हुए हैं। उन में से 9 हिन्दू थे क्योंकि उस वक्त सिख नहीं थे। गुरु गोविन्द सिंह जो दसवें गुरु थे, वे जुल्म व सितम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक फौज तैयार की और वह गरीब आदमियों की फौज थी और जैसा जनरल साहब ने एक दफा इस हाउस में कहा था कि हिन्दुस्तान के हर हिस्से से आदमियों को लेकर उन्होंने फौज बनाई थी। उनकी तालीम को बेस बनाते हुए ज्ञानी जी ने पंजाब में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था, उस को मैं खुद जानता हूं। मैं भी साथ की स्टेट में मिनिस्टर था और मैं कह सकता हूँ कि वह एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो मैं यह जानता हूं कि यहां हर सदस्य जो चाहे

बोलें यह उसका अधिकार है, यह एक डेमोक्रेटिक हक है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में अपनी कमजोरियों, अपनी नावाकफियत या कम उम्री की वजह से या मजबूरियों की वजह से वे शामिल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने भी हक दिया और इस लिए हर एक को हक है कि वह जो कहना चाहे कह दे। मगर कहने से पहले उन्हें सोच से काम लेना चाहिए अगर आपको देश को बचाना है, तो जो मैंने जो पहले कहा है उसको आप करिये। होम मिनिस्ट्री जो है, वह सेफ हैंडस में है। श्री वेंकटसुब्बय्या को जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि वे बहुत समझदार हैं, गुस्से में नहीं आते, पेशेनेट नहीं हैं और आपको चेलेंज नहीं करते हैं लेकिन सब के को-आपरेशन की जरूरत है और जो मूल जरूरतें हैं, उनके बारे में सब को सोचना होगा और फन्डेमेंटलिज्म किसी रंग रूप में हो उसके खिलाफ लड़ना होगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसी लिए इनको आन्ध्र नहीं भेजना है।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : प्रोफेसर साहिब, आन्ध्र में या कहीं भी हो, कोई कहीं भी जाएं, तो वह अपनी मरजी से जाएगा उस को जबर्दस्ती नहीं भेजा जाता। यह हमारी पार्टी की बात है। हमारी अपनी मजबूरी हो तो भेज भी सकते हैं लेकिन हम आप को नहीं भेज सकते। जरूरत पड़ी, तो उन्हें आन्ध्र भेज भी देंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो असली कांग्रेसमैन है, उस को चाहे चपरासी का काम करना पड़े और चाहे मिनिस्टर वह खुशी से करता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) : अंजैय्या साहब यहां से गये थे, तो क्या वैसा ही हाल इनका करोगे?

श्री गिरधारी लाल डोगरा : ठीक है, अंजैय्या साहब गये थे और जब उन्होंने देखा कि उन का चीफ मिनिस्टर बने रहना ठीक नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, वे कुर्सी से चिपके रहे, ऐसी बात आप नहीं कह सकते। ये हमारी अन्दरूनी बातें हैं और हमारी खूबी यह है कि जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे और जरूरत पड़े, तो हट भी जाएंगे। यही हमारी खूबी है और मैं आप के साथ और दूसरे बुजुर्गों के साथ इस में किसी कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपनी पार्टी की सुपीरियारिटी नहीं बताना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से एक विचार से, एकमत होकर फैसला करते हैं? आपकी तरह छोटी-मोटी बातों को हम नहीं देखते हैं। मैंने ज्ञानी जी के बारे में इसलिए बात की क्योंकि सतीश अग्रवाल जी ने उनके बारे में कुछ बातें कही थीं, कल की कार्यवाही में भी कुछ बातें उन के बारे में कही गईं। बेढंगी बातें कहने से कुछ फायदा नहीं है। रेलवे पर दंडवते जी की स्पीच हुई थी तो हमने कहा था कि बहुत अच्छी स्पीच है, लेकिन चंद्रजीत यादव जी की स्पीच एक कव्वाली की तरह थी। बातें उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छी कहीं, और कुछ इधर-उधर की।

मेरा निवेदन है कि जरूरी बातों की ओर ध्यान दीजिये। उनको ठीक कीजिए, हमारे विधान से अच्छा विधान आपको नहीं मिल सकता, इसमें तबदीली की आवश्यकता नहीं है।

इतना कहकर ही मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI ZAINUL BASHER (Ghazipur): Mr. Chairman, Sir, primarily, I would deal with the law and order situation in Uttar Pradesh. A lot of things have been said in this august House regarding the law and order situation there. My Hon. Friend, Shri Chandrajit Yadav, said that Uttar Pradesh has become a haven for dacoits. Many things have been said regarding fake encounters. It has been pointed out here that all is not well in Uttar Pradesh so far as the law and order situation is concerned.

The fact is otherwise. The law and order situation in Uttar Pradesh is so satisfactory as it has never been before. I would like to give you some figures through which we can see that the law and order situation there has considerably improved. The incidents of dacoities in 1977 were 4,187 ; in 1978—3,644—both years of the Janata Party rule—in 1980—3,643 and in 1981—2,858. The number of lootings in 1977 were 7,343; in 1978—6,919 ; in 1980—6,624 and in 1981—5,306. As regards murders, in 1977, there were 4,756 murders ; in 1978—5,202; in 1979—5,329; in 1980—5,422 and in 1981—5,568. The incidence of murders has increased to which I shall come later. Coming to riots, in 1977—11,290 ; in 19783—2,484 ;

14.33 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*].

Year	No. of offences
1980	27,050
1981	21,915

Total Cognisable Offences

Year	No. of offences
1977	2,22,400
1978	2,13,471
1979	2,05,644
1980	1,96,715
1981	1,89,963

Now, these people are accusing and throwing the blame on us for the law and order situation in Uttar Pradesh. But you will find that when these very people ruled that State, the incidence of crime was much more.

You must note that now the incidence of crime has been, in fact, reduced up to the extent of 25.55% over 1980 and the incidents of crime that took place in the year 1981, compared with those that took place in the year 1977-78, have substantially come down. You can find it from the percentage of crime figures.

This shows the hollowness of their attack on the law and order situation in Uttar Pradesh.

The fact is that Uttar Pradesh is the first State in the country engaged in the elimination of dacoits. Especially the Chief Minister of Uttar Pradesh and the U.P. Police have declared a war on dacoits. Never before in the histroy of Uttar Pradesh have such Herculean efforts made to eliminate the dacoit menace. The Uttar Pradesh Chief Minister has declared a war against dacoits.

We find that 20 gangs of dacoits have been wiped out.

Only 10 out of 55 districts are affected with this dacoit menace.

Uttar Pradesh is a very big State. It is the belief of people that Uttar Pradesh is infested with dacoits.

But this is not the real position. This is not the fact.

Only 10 districts out of 55 are affected with this menace.

The Chief Minister of Uttar Pradesh and the U.P. Police are firmly determined to liquidate dacoits.

We can find from newspaper reports that every day, one or the other gang of dacoits is being liquidated.

The U.P. Chief Minister has made a greater sacrifice. His brother who was the Judge of a High Court was killed by the dacoits.

The dacoits have become desperate. They have become confused, rather they have gone mad, because of the biggest onslaught on them by the U.P. Police.

The dacoits have become so desperate that they have now started killing innocent people. This is the extent to which they have gone now. They are killing sometimes innocent people, sometimes policemen, and sometimes even ordinary citizens. They have lost their discrimination and they have become indiscriminate in killing people. They are doing all this with one motive. The dacoits believe that by these indiscriminate acts both Parliament and the Assembly would be led to believe that they should demand the resignation of the Chief Minister and when the Chief Minister goes out of the picture, they would be let loose and they would be free. This is their mentality.

I wonder that instead of getting kudos and congratulations from the Parliament and from the Assembly and from elsewhere, the Chief Minister is getting brickbats. This is very unfortunate in the history of Uttar Pradesh

We must, in fact, congratulate the man who has taken up the cause of gentle people, the common people and has waged a war against dacoits and is firmly determined to eliminate dacoits once for all and we must stand behind him. He has stood for a very noble cause and, I must say, this is the first instance of a man who has stood for this noble cause for the first time in the histrory of Uttar Pradesh and of this country as a whole. Things are being said regarding encounters. One gentleman as said that 5,000 persons are being killed in fake encounters. The fact is that only 1,200 people have been killed and not in fake encounters. Dacoits and goondas have been killed. 22 gangs have been liquidated. How many persons must be in those 22 gangs ? There must be a considerable number in one gang. Only 1,200 people have been killed in encounters ; not only dacoits but goondas also have been killed in the encounters. The encounters were real. Here is a proof: about 120 policemen, including officers, Deputy Superintendent of Police, Sub-Inspector of Police, Head Constable and Constable, have given their lives ; they have also been killed by the dacoits. The policemen were killed and dacoits were also killed in the encounters. For the first time in the history of this country, the Chief Minister has taken the task on himself to see that no innocent person is killed in the encounter. Wherever he has received complaints, he has taken the police to task. Four cases of murder have been lodged against policemen where the inquiry shows that encounters were fake. Another 15 to 20 cases are under investigation. The Chief Minister has given strict orders to the police that, while eliminating the dacoits will be appreciated, if common people are killed in the encounters, the police will be taken to task. The theory of fake encounters which the Opposition is building up in this august House and outside is fake ; that theory is fake ; the encounters are not fake. I think, wonderful work is being done in U.P. We must stand behind the Chief Minister, we must stand behind the police there, we must stand behind the Government of that State.

Now I come to the point of national integration......

MR. DEPUTY-SPEAKER: I hope this is the last point you are making. You will then conclude.

SHRI ZAINUL BASHER: I will not take more time. This is the last point.

When the Moradabad incident was discussed in this House, actually this House was rocked ; from both sides of the House, concern was expressed and it was said that the communal riots should be curbed and the objective of national integration should be achieved. What happened ? The Home Minister assured the House that he would take every step to check incidents of communal violence. I must congratulate the Home Minister that communal incidents of the magnitude of Moradabad have not taken place, but at the same time I wish to point out that communal incidents have taken place since then in this country and are taking place regularly ; after every two or three weeks, we find that some incident has taken place somewhere in this country. Recently in Sholapur, Poona, Kanyakumari, Baroda and Aligarh, we found, there were communal disturbances. Reports of communal disturbances are coming from various parts of the country. It means that we have not succeeded in our efforts to curb incidents of communal violence. Why is it so ? I want to know whether we have gone into the depth of the problem or not. Only by deployment of military, BSF, CRP and Police, the communal incidents cannot be curbed. For that purpose we shall have to go into the depth of the problem to find out who was responsible for the communal incidents, why communal incidents are taking place. We have a report on the Jamshedpur riots. There was a Commission appointed and its report was submitted. I do not remember the name of the judge ; Mr. Banatwalla will enlighten us. In that report which was submitted, the RSS was indicated. The report says that the RSS was responsible for the communal riots. For the last 20 years, in this House and outside, open accusation is being made against the RSS that they instigate the communal disturbances, they are behind all communal disturbances in this country. What are we doing to check their activities ? Have we done anything ? I ask my own Congress Government. Regarding Janata Government, the RSS formed part of Janata ; therefore, I cannot say anything to them. But what has out Government done to curb the activities of the RSS ? These figures will show that, instead of curbing the activities, of the RSS, its strength has been allowed to increase day by day...

MR. DEPUTY-SPEAKER : You wanted to speak on national integration ;

SHRI ZAINUL BASHER: It is part of the Home Ministry. In 1979 there were 6.33 lakhs of RSS members ; in 1980, they were 10 lakhs ; in 1981 the figure went up to 15 lakhs. In 1979 there were 10,000 RSS shakas and in 1981 there are 16,000 RSS shakas. What are we doing ? Have we put any curb on the RSS activities ? This is one point where cooperation from the Opposition will be forthcoming. We are talking about cooperation from the Opposition parties. Except BJP, every other Opposition party will cooperate in that effort to curb the activities of the RSS. We have not forgotten that the Janata Party itself broke on the issue of RSS. Those who left the Janata Party accused the RSS for the communal incidents and other things...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude.

SHRI ZAINUL BASHER: I am talking on a very important subject.

MR. DEPUTY-SPEAKER: A Minister has to intervene at 3-00. There are others also who have to speak. If you take more time, you will be depriving the other Members of your Party of the opportunity of speaking and they will find fault with me. That is why I am requesting you. Otherwise, it is a pleasure; I can hear you for hours together.

SHRI ZAINUL BASHER: I am talking about national integration. This is very important. They are not curbing the activities of the RSS. At least, please do not curb me. I must say something. The activities of the RSS are increasing. The cooperation of the Opposition on this is forthcoming. Why can't we deal with them? The Home Minister is going to intervene. Mr. Venkatasubbaiah is a very great gentleman; he espouses the cause of the minorities very much. I would like to him to enlighten us about it. The cooperation of 98 per cent of the Opposition is forthcoming on this issue of RSS. Why are we not taking any action against them? Why are these communal incidents taking place? Why is Baroda burning? Why is Kanyakumari burning? Why is Aligarh burning? What happened in Moradabad? Are the results not coming to the Government? Are the reports not coming to the Government? Why are they not taking action against the RSS? What are you doing about the Vishwa Hindu Parishad? Some conversions took place in your own State of Tamil Nadu and about a few hundreds people were converted. Poor Harijans were converted from Hinduism to Islam. They had their own reasons. Who is responsible for their conversion? Was it for foreign money, as it is alleged? If the allegation is serious, why did you not inquire into the matter? Name the foreign money. Was it foreign money? No, it was not foreign money......

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are putting question and you are answering it yourself.

SHRI ZAINUL BASHER: It was their own deed. I am talking of Hindu fanatics......

MR. DEPUTY-SPEAKER: It should be replied to by the Minister.

SHRI ZAINUL BASHER: It is Hindu fanatics. It is their own deed. Because of that the Harijans got converted. Now the bogey has been raised in this country that Hinduism is in danger. In those pre-partition days the bogey raised was that Islam was in danger and the country was partitioned. Now a bogey is being raised that Hinduism is in danger. I fail to understand. When Non-Hindus ruled the country for thousands of years, Hinduism was not in danger. But when 80% of the population who are Hindus are ruling the country, how can Hinduism be in danger? This is a trick. This is only to instigate communal feelings, in the same manner in which the Muslim League instigated the communal feelings in pre-partition days by raising the bogey of Islam being in danger. The Government must take cognisance of it and deal with it firmly and deal firmly with those who are responsible for that.

Lastly, I would like to say that our Government should apply its mind thoroughly and a high power commission headed by a Judge of the Supreme Court should be appointed to inquire into the activities of the RSS as also the activities of the Vishwa Hindu Parishad or any other communal orgnisation. A committee of inquiry under the Chairmanship of a Supreme Court Judge should be appointed to pinpoint which organisations in the country are communal, what is their past history, what they have done and what action against them is being proposed by the Commission. This is very important and when the Commission pinpoints the organisations, they should be banned.

With these words, I thank you, Sir.

PROF. P. J. KURIEN (Mavelikara): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, this is a discussion on the Home Ministry. Ours is a constitution not fully federal nor is it fully unitary, but it is a quasi-federal constitution. In such a set up the Home Ministry has to play an important and key role. The framers of our Constitution have envisaged a secular and free India. Due to historical reasons in this country, there were sections of downtrodden people who have been exploited for long and so, the Constitution-makers have provided for them sufficient protection in our Constitution. They felt that these weaker sections and other religious minorities are to be given protection according to our Constitution. Why I raise this point here is that, in this House, many a time, we have formed that there was a tendency on the part of the Home Ministry, and, even sometimes, from the Chair,—I may be excused to say so—that whenever the question of atrocities on Harijans and other minorities came, to treat it as a law and order problem. But, I would like to remind the Home Minister that giving sufficient protection to the Harijans and minorities is a constitutional requirement and so, the Central Government cannot shirk that responsibility. I do admit here that the law and order issue is a State subject. But, when atrocities are committed on Harijans and when there are communal riots where the minorities in large numbers are killed, what should be Centre do ? Should it keep mum ? I am sure the Central Government has sufficient inherent and constitutional powers to immediately action.

I now come to Kanyakumari incidents in Tamilnadu. It is a pity that after thirty five years of Independence, our country is not rid of communal riots. At the time of Independence, we have to devide the country and on both sides, a number of our fellow men were killed. Now, even after thirty five years, from the borders, the communal tension has spread to all parts of our country. It has even reached upto the South—Cape Comorin, the southern—most part of our country. This is a very sad state of affairs. I have no hesitation to say that the Central as well as the State Governments have failed to contain these communal riots. At the same time, I would also like to add that the R. S. S. and other communal parties are also responsible for injecting communal feelings in the minds of our people.

In Kanya Kumari District tension still is prevailing and the Tamilnadu Government, as I understand it, has failed to give protection to the minorities and the weaker sections of the people including fishermen. I fail to understand why the Central Government has not intervened. If my information is correct, the R.S.S. is behind creating communal riots. In Kerala also what happened was this. Kerala was so far a tension-free State. There was no communal trouble or riot. There too the R.S.S. and B.J.P. have extended their activities. They started the killings and counterkillings in Kerala. During the last two years hundreds of people were killed. Of course, I do not agree with my Marxist friends in their theory that one killing should be retaliated by another killing.

AN HON. MEMBER: That is not our theory.

PROF. P. J. KURIEN: In Kerala that is what has happened. Both the Marxists and the RSS were counting the number of heads. With all that I have no hesitation to say that it is the spreading of the RSS activities in Kerala that has brought about this kind of communal clashes and political clashes into Kerala. So, I fail to understand why does the Home Ministry not take note of it and take stringent action against those who are indulging in communal riots and mass killings.

Sir, yesterday Mr. Charanjit Yadav mentioned that there should be special courts to punish these culprits of communal riots. I support that view. There should be special courts and those who indulge in communal riots should be booked and given severe punishment.

Sir, we always talk of Gandhiji. But I would request all the political leaders both sitting here and there—including the BJP—to atleast follow Mahatmaji in one respect. Let us take a pledge that no political leaders or any political party will propogate or spread communal tension in order to make political capital out of it.

If such a decision is taken by leaders of all political parties then I am sure this country will attain the goal which Mahatmaji had in mind.

Sir, I would like to bring to your notice a very gross discrimination meted out to a certain section of our people in our country. Articles 15, 16 and 25 of our constitution highlight the secular character and assure equality to all citizens. I quote Article 15 :

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, etc.

Article 25 says :

"......all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion."

But, Sir, under Article 341 of the Constitution the President of India has promulgated the Scheduled Castes Order of 1950 wherein it is mentioned :

"No person who professes religion different from Hindu or Sikh religion shall be deemed to be a member of a scheduled caste."

I have no objection to that but what is the consequent effect. Consequently the rights and privileges enjoyed by the Harijans are denied to them when they get converted to another religion or change their faith. You know, Sir, that religion is a matter of opinion and I know so many people who have changed their religion three times. In Tamil Nadu also such cases of changing of religion have taken place. That being the case, how can you say that when a Harijan is converted to Islam or Buddhism or Christianity or any other religion overnight he has come out of his social backwardness? No such thing takes place simply because he has been converted to some other religion. Here is a clear case, according to me, of discrimination against a particular section of the people.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude. Your time is over.

PROF. P. J. KURIEN : I have taken only 5 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have taken full time; when you speak you don't note this.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPT. OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : We are watching you when you are speaking...

AN HON. MEMBER : Big brother watching.

PROF. P.J. KURIEN : What happens? Faith is changed; opinion is changed; the man's social status remains the same: that has not changed and when that has not changed why do you discriminate on basis of religion? To me it appears that it is opposed to Art. 15 and 25 of the Constitution of India. I request the Home Minister. I request the Prime Minister, I know she is the symbol

[Prof. P. J. Kurien]

of secularism. I appeal to them to bring in the necessary constitutional amendments. Whatever benefits are given to Harijans should not be denied to them even if they change their religion. Benefits intended for these sections of people should be extended to them irrespective of whether they change their religion and whether they belong to X religion or Y religion. This is my plea.

Now I trun to Kerala affairs. The Kerala situation has been discussed by many Hon. friends here. The Governor of Kerala dissolved the Assembly as per Article 174 of the Constitution. Some of our friends criticised the action of the Governor. I feel that the Governor was perfectly within her rights and fully empowered to dissolve the Assembly ; nobody else has to exercise the judgment; only the Governor is the judge of the situation; only she or he should be satisfied. And this has been the tradition and the practice which we have been following in this country since our independence. What happened when the Janata party was inpower ? Even when they were inpower the Governors took certain decisions. Now, criticising that decision, to me, appears to be not proper. I have to ask one question : What is the argument that they have advanced ? They said, the Assembly should not have been dissolved. This is what has been demanded by the opposition. A few days earlier, they themselves were demanding the dissolution of the Assembly ; and this was the case till the moment they got one Member from the ruling party ; immediately they got one MLA from the ruling party, they started demanding, there should not be dissolution of the House. Their argument is : If the ruling party has got majority then Assembly should be dissolved. If not, the Assembly should be retained. This is a funny argument. What happened was this: In a House of 141, Mr. Karunakaran had a majority of 71 including the Speaker. At that time the opposition were demanding that Assembly should be dissolved. That demand was continuing. But what happened on a fine morning ? From 71 Mr. Karunakaran's party strength was reduced to 70. Mr. Nayanar's party strength was increased to 71. Immediately the demand came up saying : Assembly should not be dissolved, because it suits them. Why this double standard ? If this is not double standard, what else is double standard ? It is a clear case of double standard. Now they are saying that the Assembly should be retained not for forming a Government but for Rajya Sabha election. Sir, in this connection I am reminded of a story. I don't know whether I can say it here, but I am saying it here. One young man came and told his father one fine morning : Father, get me married because I want a servant in the kitchen.

That was the request of the young man to the father. Likewise they are saying keep the Assembly with us as 71, so that we will vote in the Rajya Sabha. I say that is not your main function. Your main function is forming a viable Government.

SHRI CHATURBHUJ (Jhalawar) : Sir, I am on a point of order.

SHRI G.M. BANATWALLA (Pounaria) Sir, under what Rule is he getting up ?

SHRI CHATURBHUJ : Sir, I am rising on 376. On the part of the Opposition, the plea was that on the recommendation of a minority Government, which has already become a minority, the Assembly should not have been dissolved and the Governor should have ascertained....

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is a matter of opinion. That is all right. There is no point of order.

PROF. P. J. KURIEN : Sir, the Hon. Member speaks of the Constitution. Does Article 174 of the Constitution say in that way, as he said ? Minority or majority should be proved on the floor of the House ; otherwise the Governor is the Judge. No other precedence you can quote. Don't try to mislead.

Sir, I congratulate the Home Ministry and the Government, whoever it may be, for taking that bold step. But, I have one request that steps should be taken to conduct an election in Kerala immediately. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : As you want election in West Bengal, he also wants election there. What is there ? You must support him.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, there is a difference about the timing. We were not opposed to the dissolution of the Assembly but the timing of the dissolution.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi) : Sir, Shri Vajpayee is not against dissolution of the Assembly. Does he mean the same thing about West Bengal also ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, he has not thought about it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I thought we were discussing Kerala.

PROF. P. J. KURIEN : In Kerala, Vajpayee's men are being murdered by Marxists.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : We will settle that. You settle your own thing.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think Vajpayee has felt that it was not an auspicious time. That is what I say.

PROF. P. J. KURIEN : Sir, election should be conducted as early as possible so that after the election, Rajya Sabha election can also be conducted.

Sir, this is discussion on the Home Ministry. I have to say one very important thing i.e. corruption in the country. Many people were talking about corruption. Of course, there is much talk about corruption. And the pity is that the corrupt men get more publicity and those who are not corrupt, will not get publicity. This is what is going on in the country. But even then, corruption from the top to the bottom is a reality. Some strong steps have to be taken to prevent corruption. There is corruption among the political leaders; there is corruption among the Administrators. I fully agree with Shri Tytler that there is a lot of corruption among the Administrators and the political leaders. But it is the duty of the Home Ministry to consider that aspect. Further there is widespread propaganda about corruption. The whole atmosphere is viciated with corruption. The people have, therefore, got a psychological acceptance of corruption. Unless the Home Ministry comes forward with specific proposals or with certain bills; and not only get them passed, but implement them with sincerety, nothing can be done. Therefore, I request the Home Ministry to come forward with some specific proposals or bills and implement them sincerely so that at least to some extent corruption is removed. Otherwise, I am sure, this country will go to dogs.

AN HON. MEMBER : No, it will not go to dogs; it will go to heaven.

PROF. P. J. KURIEN: I request the Home Minister to come forward with some anti-corruption Bill so that some effective step is taken to root out corruption.

Sir, the question is, why corruption is prevelent. To that my answer is that ours is a democratic system and there is an election process. I thought when the Janata Party with Shri Morarji Desai as Prime Minister came to power, of course, blessed by the late Jayaprakash Narayan, the great man, I thought some efforts will be made to reform the election procedure in the country so that money power in election is reduced. I also thought at least they will bring in an antidefection Bill or something by which corruption can be curtailed to a minimum. But I was disappointed to see that they ruled for three years, but nothing had come out.

SHRI SATYASADAN CHAKRABORTY : Sir, on one point of clarification.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no time. He is not yielding. Are you yielding. (*Interruptions*)**

PROF. P. J. KURIEN: Sir, I am not yielding (*Interruptions*)**

Even for the last two years, when I was here I always have my independent opinion. You cannot say that. Sir, that should be removed.

Please expunge that. That should be removed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will go through the records.

SHRI C. T. DHANDAPANI : He did not yield to him. So, his remarks cannot go on record.

PROF. P. J. KURIEN: Sir, the remark should be removed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Did you yield to him?

PROF. P. J. KURIEN: I did not yield to him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. Whatever he has said would not be recorded. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : As you have said, you have not yielded to him, it will not go on record.

PROF. P. J. KURIEN : Sir. I would request the Home Minister that he should come with concrete proposals for reforming the procedures so that money power is reduced in election. That is the only solution and remedy for reducing corruption in the political level and otherwise.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Only what Shri Farooq Abdullah is going to say will be recorded.

DR. FAROOQ ABDULLAH (Srinagar) : Mr. Deputy-Speaker. Sir, I rise on the Home Minister's Demands' debate.

I will straight go to my State of Jammu and Kashmir. A lot has been said in this House by Members from that State. I will particularly refer to Ladakh. I do not deny Ladakh is backward. I do not deny that Ladakh is large as far as the area goes. But what I would like to say is let us not divide ourselves on party issues, but see whether this Government that has been in power since 1975, has done anything or not. The problem here is that even when district of Ladakh was divided for the Developmental sake of that area, it was dubbed as communal as if religion plays of part for development of India and all Hindu areas must not develop and all Muslim areas.......

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is not yielding. Please sit down.

(*Interruptions*)**

**Not recorded.

**Not recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not anything. Please do not record spoil.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not allowing you. That is not the way. Please sit down. Do not record whatever he says. Please do not record.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister is going to reply. Why do you take the law in your hands ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please listen. The Minister is going to reply.

(*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH : This shows the intolerance.

SHRI P. NAMGYAL *rose.* :

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Don't record what he says. Don't record anything. I am not permitting him. Nothing will go on record.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: May I make an appeal to you, Mr. Namgyal ? Let Dr. Farooq Abdullah speak. You had your say. Let him have his say.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Don't record what Mr. Namgyal says. This will not go on record. You also need not reply.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER ; Please take your seat.

DR. FAROOQ ABDULLAH : For God's sake, please understand.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Dr. Abdullah, please address me.

**Not recorded.

DR. FAROOQ ABDULLAH : I am sorry ; I apologize.

When I came to this House two years ago, I thought in this House we made India. We are not merely Kashmiris or Ladakhis, or anybody else or people belonging to National Conference or Congress. But to us India matters. If India dies, we die. But, unfortunately, we are not Indians. We belong to National Conference or Congress. That is all that matters.

It is all right upto 1947.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Don't get emotional.

DR. FAROOQ ABDULLAH : It is all right till then because we had the British to throw out. But to-day, the time for agitation is over, because we have to build India—not for us, but for the generations which will follow us. Let us give them the India of Mahatma Gandhi.

Now about agitation for Ladakh. I tell people here : "Give us more money, and Ladakh can be made into whatever you want it to be made." We said : "For six months, Ladakh gets locked up ; and the only way you can get to Ladakh is by plane. And many times, even aircraft cannot get there, because the weather is bad." They said tunnels should be built. The Central Government put it down saying : 'No ; for just one lakh people, you cannot spend so many hundreds of crores for tunnels.' The second suggestion was about ropeway.

SHRI P. NAMGYAL : *rose.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Namgyal, please sit down. Dr. Abdullah, you do'nt give any reply whatever to Mr. Namgyal. What he says will not go on record.

(*Interruptions*)**

**Not recorded.

MR. DEPUTY SPEAKER : The Minister has to reply.

डा॰ फारूक अब्दुल्ला : यही तो मुश्किल है कि ये समझते नहीं हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं । मैं कभी यह नहीं करना चाहता कि लद्दाख को मत बनाइये । मैं कहता हूं सारे हिन्दुस्तान को बनाइये । लेकिन फायदा क्या है ? जब ये तूफान की तरह से बोल रहे थे तब हमारी पार्टी ने इनको इन्टरप्ट नहीं किया । आज जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरा गला दबाना चाहते हैं ।

Two percent is the population, as compared to the whole State for them. And financial allocations have gone up to 6%. The nett sowing area of that place was 17,000 hectares in 1974-75. To-day we have raised it to 20,000 hectares. The number of Veterinary units and sub-units in that area has been raised from 52 to 129, to-day. The cattle population has been increased from 0.36 lakh in 1972 to 0.44 lakhs in 1977. The veterinary sub-units and other units have also gone up from 52 to 129. The number of primary schools has also been increased from 226 to 315—for a population of just 50,000.

SHRI P. NAMGYAL :**

MR. DEPUTY SPEAKER : This is not Kashmir Assembly.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY SPEAKER : Do not record whatever Mr. Namgyal says. (*Interruptions*)**

DR. FAROOQ ABDULLAH : When in Leh an agitation was started this year, they destroyed the property worth Rs. 11.54 lakhs which did not belong to only one person but it belonged to the people of this country. When the Minister's vehicle was burnt and the moment they noticed that the shops would also be burnt by that vehicle because it had 40 litres of petrol in it, they went to extinguish the fire. The property of the Government did not matter, the record of the Government did not matter; the vehicle of the Government did not matter, but the shops did matter. The point here is are we not thinking in terms of what we are building for tomorrow or are we thinking in terms of destroying...... ?

(*Interruptions*)**

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Who started the agitation ?

DR. FAROOQ ABDULLAH : The agitation was led by the Hon. member himself; and not only this, the people who have Buddhist faith do not believe in violence for Buddha's teaching is non-violence. And they went to the monasteries to bring the lamas to agitate; and two of the big monasteries refused to send lamas for agitation ; and they said, "Everywhere you hold such things for your own ends; we are not giving you any lamas." (*Interruptions*)**

And he is one of them. I tell you that he organised it; he should know about it.

(*Interruptions*)**

I have mentioned it. You go and see it for yourself.

(*Interruptions*)**

Secondly, in Kishtwar, an agitation was started demanding separate District for the area and Degree College. Sir, it is Government's policy as laid down by the Jha Commission that Education system of 10+2+3 must be implemented for the sake of not providing army of unemployed graduates and education after 10th Class must be strictly

**Not recorded.

**Not recorded

limited for people who have ability to go into Professional Colleges and University education and the majority should be diverted towards I. T. Institutions. Regarding District a Commission has been appointed under the Chairmanship of ex-Chief Justice, Mr. Wazir, to look into merits and demands of each case, be it Kishtwar or any other region of Jammu and Kashmir. Then why this agitation ? Wood worth 30 crores was not allowed to be transported and property, which included buildings, Government vehicles and wood was burnt amounting to loss of over a crore. It was because of this Government took urgent action so that the wood if not transported now would have gone to Pakistan by the middle or end of this month when river water rises.

On one side, we have the external danger. Every day, we talk of it. Even today we are saying that the arms which the other countries are going to get are not going to be used against Russia; they are going to be used against India. On one side, we have the external danger ; on the other side, we are creating internal dangers. How many fronts are we going to open ? Then 1975 Accord should not have taken place; then it should have been turned down and burnt because only one party's flag must fly from the right to the left and from the East to the West. You tell us where we are wrong ; and if we are wrong, we will try to mend ourselves.

When the Hon. Minister went there, he saw the area. He went by a special plane. The Hon. Minister did not have the time to see the Governor or the Chief Minister to tell us what he saw. He did not have the time to see the Governor or the Chief Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : Sir, I spoke to the Chief Minister.

DR. FAROOQ ABDULLAH : On the phone.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I was to attend an urgent meeting in Delhi.

I did not violate any protocol. I saw to it that I paid my respect to Sheikh Saheb. I spoke to him on phone. I do not want to enter into any controversy over this. When I was going, naturally my tour programme would go to the Ministers. Though there is no protocol, no State Minister came to the Jammu airport. Even then, I took the initiative. I spok to the Chief Minister ; I paid him my regards. I do not think my friend will have any complaint in this regard so far as I am concerned. The Home Minister and the Government of India will preserve and maintain all protocols. Whatever respect we have to give, we will give to the Chief Ministers. I wanted to keep the record straight.

DR. FAROOQ ABDULLAH : I will not enter into this controversy. I would like to say to the Minister that what we are doing in Kishtwar is not for the sake of winning election but for the sake of maintaining law and order.

SHRI P. NAMGYAL (Ladakh) : No Minister of your Government visited that area so far. How long has that agitation been going on ! (*Interruptions*).

DR. FAROOQ ABDULLAH : We talk of corruption. Corruption was mentioned a lot here. But I would like to ask them how much of parallel economy is there in India. Have we been able to control that parallel economy of black money which is there? Are we able to win or lose elections without that? We have a law in Jammu and Kashmir—the Anti-Defections Law. Will this

[Dr. Farooq Abdullah]

august House not have that Bill introduced here for the sake of future India? I request the Government; would they not possibly introduce this Bill so that members cannot be bought and sold? I am not speaking as a National Conference man. I am speaking as an Indian. I have no animosity against you. I will never have any animosity against you. But we are destroying India by this corruption. We are fighting this corruption. We are trying to fight it. But believe me, nowhere, not even in the Railway Station can you get a berth unless you pay something to the guard even if your reservation has been done. I am telling you. Even in Delhi Station....

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do you think it is the House or something else? It is not that we are discussing somewhere else.

डा० फारूक अब्दुल्ला : हुज़ूर, यही तो अफसोस है मुझे कि जमात का सोचा जाता है, हिन्दुस्तान का नहीं। जमात का क्या सोचते हो, हिन्दुस्तान का सोचो। मैं कहता हूं कि अपने सैक्रेटरी के साथ वहां खड़ा था, रिजर्वेशन यहां से की गई थी, जब गया उसके सामने और कहा कि मुझे रिजर्वेशन दो, मेरी बर्थ है, वहां पर क्लर्क था, उसने कहा कि यह हमारे एम० पी० बैठे हैं, 10 रुपये निकालो तो बर्थ मिलेगी।

मैं करप्शन के खिलाफ बोलना चाहता हूँ, आप करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, फिर वजह क्या है कि करप्शन हट नहीं सकती? मंहगाई बढ़ती जाती है, पैट्रोल के दाम बढ़ते जाते हैं, हरेक चीज के दाम बढ़ते जाते हैं, तनख्वाह बढ़ती जाती हैं, फिर भी करप्शन नहीं हटती? (व्यवधान) खुदा के वास्ते इससे मत लड़िये। मैं जो कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कल वहां जाना है। जो लोग आज...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please address the Chair.

DR. FAROOQ ABDULLAH : Irrespective of our party, it is our duty to see that wherever there is corruption, we should throw it out. But don't think that elections can be manoeuvred or won by....

(*Interruptions*)

SHRI P. NAMGYAL : What about this ?

DR. FAROOQ ABDULLAH : He has raised an issue which his own party has produced. It is not produced by anybody else. I can prove it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Don't reply to him. Now, try to conclude.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह लगातार टोकने और दखल देने से बहस नहीं चल सकती। गृह मंत्री अपने सदस्यों को समझाएं। यह तरीका ठीक नहीं है। मैं बहुत देर से सब्र कर रहा हूँ। ये लोग सदन को नहीं चलाना चाहते हैं। अगर उनकी यही मंशा है, तो फिर सदन नहीं चलेगा।··(व्यवधान)

DR. FAROOQ ABDULLAH : I would like to tell him that when the elections come, the result would be before him. Let them publish whatever books they can. The final decision is that of the people. What I request you, since you are the ones who have to watch the interests of the nation : is this : please don't be taken for a ride for mere party ends. Please consider India first and then the party.

AN HON. MEMBER : You are protesting too much.

DR. FAROOQ ABDULLAH : I am not protesting enough, because the day I protest, you will know.

In conclusion, I thank the Home Minister for listening to me and I hope that he will pay attention to the few things I have said. I did not touch on communal elements. They need to be dealt with on both fronts—the Muslim elements as well as the Hindu elements. You cannot fight one alone. You have to fight both the elements. Unless you fight them, you will not achieve what you are trying to achieve. Unless you face them boldly, there is no question of saving India.

SHRI JAGDISH TYTLER : I was very happy to hear Dr. Farooq Abdullah speak about India. We are all one and we will all get together and : remove Article 370 from the Constitution. (*Interruptions*)

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : मैं अपनी तरफ के मेम्बरों से प्रार्थना करूंगा कि जब वे बोल रहे थे, तो उन्हें किसी ने नहीं रोका। श्री नामग्याल का यह बिहेवियर अच्छा नहीं है। मैंने बार-बार हाथ से इशारा किया, लेकिन कहा नहीं। मैं श्री टाइटलर से प्रार्थना करूंगा कि इस एक इस्यु पर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है हिन्दुस्तान के गृह मंत्रालय के कामों पर। अगर उसमें प्रान्तों का कुछ रेफरेंस दिया गया है, तो देने दीजिए। डा० फारूक अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में क्या कहा है, उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी, तो मैं कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Venkatasubbaiah.

(*Interruptions*)*

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not permitting anybody. Nothing will go on record. Only the Minister of State will intervene now.

(*Interruptions*)*

MR. DEPUTY-SPEAKR : The Minister will reply to the speech.

I am not permitting anybody.

(*Interruption*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : No personal expalanation. I am not permitting anybody. I have called the Minister.

The Minister would like to intervene.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, every year, the Hon. House will have an occasion to discuss scrutinise, analyse, criticise and also compliment the Demands put forward by various Ministries. The Home Minisitry Demands are being discussed for the last three days. We have received many bouquets and brick-bats. This helps us in analysing the situation further and also to put up a better performance so far as this Ministry is concerned.

We have the good fortune of having a Prime Minister who heads this Government, who symbolises the aspirations of the people and who has completely identified herself with the aspirations and urges of the common man. Our Ministry is headed by a freedom fighter, an administrator and a man who has committed himself to the secular ideas of this country. I have got the privilege to work as his colleague. In a way, our Ministry represents the north, south and east.

AN HON. MEMBER : What about west ?

*Not recorded.

**Not recorded.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : नार्थ में सब आजाता है

The discussion has been opened by a prominent Member of the CPI (M), Shri Niren Ghosh. He spoke with great gusto. He brought out many points. He has criticised the Government of India and according to him the authoritarian rule of one person. He has listed many acts of omission and commission. He has also said that West Bengal is being discriminated against. So, he went on chargesheeting the Government. I was wondering whether he would bring an adjournment motion here on the failure of our Prime Minister for not forging unity among the opposition parties.

Fragmentation leads to frustration. Frustration leads to cynicism. I only hope that the opposition parties make valuable contributions to the debate and whatever constructive contributions they make, I assure on behalf of the Ministry and the Government of India, that it will be given the utmost consideration.

I am not going into the working, politics or functioning of the various opposition parties, but every time we are being accused of having only one leader. We cannot afford the luxury of so many leaders and going in the way of those parties.

We are proud of our leader. We have a leader of not only national, but international fame. We know that Panditji gave a sense of identity to the north-eastern region. We have been trying to bring them into the mainstream of our national life. It is being pursued by our great Prime Minister. We should not also forget the fact that our Prime Minister had said that what Parliament has done by integrating Sikkim is wrong. We have got that example also. That is why I am telling you that national integrity and secular and democratic ideals are very dear to us.

Several Hon. Members have referred to the fissiparous tendencies and anti-social elements raising their ugly heads in order to create conditions that go against the sovereignty and integrity of our country. Government is well aware of those facts. It is our Prime Minister who revived the National Integration Council. We have constituted a separate Sub-Committee on Communal Harmony.

One Hon. Member asked : when co-operation is extended by the opposition, why is that not being taken ? The very fact of having a Sub-Committee on Communal Harmony and reviving the National Integration Council is proof positive, if any proof is needed, how serious and honest we are in our attempt to take the co-operation of the opposition to maintain communal harmony in this country.

In this very House we have passed an Act, the Special Areas Disturbances (Special Courts) Act, whereby the Government has sought to take concurrent power to declare a particular area a disturbed area. Even now the State Governments have got powers to declare a particular area a disturbed area and set up special courts for speedy trial of offences committed and disturbances like communal riots. So, the State Governments have been already empowered and the Bill which we have passed has gone to the Rajya Sabha, which has to pass it.

Then I want to refer to another point raised by Shri Niren Ghosh. He said that nearly 20 to 21 Bills have been held up for want of assent by the President. I think my Hon. friend is not correct when he made this allegation in the House. Out of the 12 Bills received from the West Bengal Government, 5 Bills are pending for want of clarification from the West Bengal Government. The remaining 7 Bills are under consideration, in consultation with the concerned administrative Ministries or Departments.

It is not as if we have made an exception, so far as West Bengal is concerned. We have cleared 145 Bills. From West Bengal we have cleared 21 Bills and 32, Sir, from your own State of Tamil Nadu. When Bills are passed on to the Central Government for the assent of the President, assent cannot be given as a matter of course. We have to consult the Law Department whether it infringes any of the provisions of the Constitution. All these matters have to be looked into. While we do not want to come in the way of the autonomy of the State Assembly or State Government, when they pass legislation, we have to see whether they are in conformity with the principles laid down by the Constitution..... (*Interruptions*) We take only that much time which is necessary to scrutinise those Bills. There is no exception in the case of West Bengal.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have made certain allegations and he has replied. Why can't you keep quiet? If you are raising for any State how can he reply? No, that is not possible.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Just a clarification.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You note it. That is all.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, my friend, Shri Atal Bihari Vajapayee, is here. About the holding of elections to the Metropolitan Council he said something. The legal position is very clear, I need not over-emphasise it. Under Section 15 of the Representation of People Act, the Lieutenant Governor of Delhi has to call for elections to the Metropolitan Council in consultation with the Election Commission. After accepting the recommendation by the, Lt. Governor the President issued an order extending the suspension of Metropolitan Council for a period of six months and operation of certain sections of the Delhi Administration Act, 1966.

Sir, in the absence of the Metropolitan Council the Government has already taken action to constitute a Committee under the Chairmanship of the Home Minister to look into the problems of the people residing in the walled city of Delhi. The Committee will make a study of the living conditions of the people in the walled city of Delhi and initiate correct measures and programmes of action to improve the conditions and monitor progress of the implementation of the measures adopted. With this broad objective the Committee will look into the specific areas, mobilise manpower and financial resources of the Delhi Administration and the various statutory bodies and ensure the speedy implementation of various schemes and programmes.

SHRI ATAL BIHARI VAJAPAYEE: Why only walled city ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I am coming to that. (*Interruptions*). Please give me the benefit of your patience. Let me complete it and then you can ask.

Sir, another question also was raised whether Delhi will have an Assembly or not. The members of our Congress Party and also other Members of Parliament have met the Home Minister. They have also been pressing this claim of an Assembly for Delhi.

SHRI JAGDISH TYTLER: It is in the Manifesto.

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): And we are going to ask for it. Today, I am going to speak.

(*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJAPAYEE: There was unanimity on the Assembly issue. But why have you wasted two years ? Because you want to postpone elections, now you are talking of Assembly.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : May I tell this to my Hon. friend ? I do not know about other parties, but so far as our Party is concerned and so far as our leader is concerned, we will never hesitate to face the people. We know that the mandate will be in our favour. Let him not be under the impression that we are going to avoid elections. We have got the massive mandate. We did not act....(*Interruptions*).

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You don't hesitate to meet the people. Only you choose the time. Is it not ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Sir, the choosing of the time is the prerogative given under the Constitution. We did not take recourse to dissolving six Assemblies under their rule, though we had a majority in the State Assemblies. They are talking of majority and minority. When the Janata Party was in power with a stroke of pen irrespective of the fact that our Party was in a majority in six States, they dissolved the Assemblies there on the specious plea .,...(*Interruptions*).

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : But what prevents you? With such a mighty leader and dynamic leader and people behind you why don't you....(*Interruptions*). You have only a mighty, dynamic, world leader.
(*Interruptions*)

SHRI P. NAMGYAL : I have not been allowed to say anything...
(*Interruptions*)

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Your Government has installed a minority Government in Assam and Kerala.
(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down. Why is everybody intervening ? Mr. Satish Agarwal has already intervened. Your name is also here. Everybody is talking. How can he reply ?
(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no. Please sit down. There will be other speeches and then the Minister will reply again. We can not conduct the proceedings this way. When the Minister replies, every one of you has got to hear very patiently.

Then only you can get some points. Every now and then you are jumping up.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Shri Halder is my good friend. He wants to provoke me and get the best out of me. I hope he will not misunderstand me.

We do not want to follow that example. We will never do that.

Constitutionally what the Governor has done, whether it is Kerala or Assam, our friend has quoted the relevant provision of the Constitution. I do not want to say more than that.

I have been interrupted. I would request my friends to give me the benefit of their patient hearing. They may say whatever they want to say because the debate will follow. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot put words in his mouth.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : The difficulty with these parties is—though they have All-India nomenclature, none of them have got All-India perspective. All of them are confined to one State or two States. That is their difficulty. They do

not have a comprehensive outlook of a national party. That is the difficulty with them. That is the great difficulty. What can I do ? It is not my fault. They are only confined to a few areas.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Your difficulty is you are so big that you cannot see the States.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : They have taken the loan from the IMF. It is the national outlook of Shri Venkatasubbaiah.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : This matter was considered in 1980. There is a proposal to appoint a Committee of experts to make recommendations for re-structuring of the existing set up with a view to making the administration more cohesive and reducing the overlapping of functions of the various agencies in Delhi.

The demand of the Members of Parliament is there. They had a discussion with the Home Minister and this matter is very much engaging the attention of the Government.

About other Union Territories I must say a word because these are under the direct charge of the Government of India and they are far flung, they require more attention so that they may be brought progressively into the main-stream of our national life. We have been giving increasing attention to the developmental requirement of the union territories which are the direct responsibility of the Central Government. As against Rs. 654 crores spent on the nine union territories during the Fifth Plan, the Sixth Plan envisages an investment of Rs. 1646.34 crores. Government are also aware of the fact that remote and backward union territories deserve particular attention. In fact among the union territories Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands have the highest per capita outlay in the Sixth Plan. Development of infrastructure for this continues to occupy an important position in the scheme for the development of these union territories.

Provision was made in the Annual Plan of the Lakshadweep administration for purchasing a new ship in replacement of the old one. The ship has been purchased and his undergoing modification to suit the requirement of the mainland—Lakshadweep services. The ship is expected to be brought in service by April/May, 1982. Similar provision for buying a ship for the mainland-Andaman Sector has also been made in the annual plan for Andaman administration. Negotiations are on for purchashing the ship.

We have taken steps for administering and giving socio-economic content to the Union Territories that are under the direct charge of the Central Government.

About the law and order situation in Delhi especially discussions were held in this House. Calling Attention, questions, have been put. We are very much conscious of the fact and we have been taking several steps to tone up the administration and also to see that the administration must be made to keep pace with this growing phenomena of crime.

16 hrs.

As I told earlier, the crimes have become more sophisticated and we have to keep in tune in detecting those offences. With regard to bank dacoities and robberies, the Home Minister while replying to a call attention, here, has said that it is being contemplated to have a bank security force so as to give more security to

[Shri P. Venkatasubbaiah]

the banks and other public institutions where these dacoities have taken place.

A small committee with the Additional Secretary of the Home Ministry as the chairman, has been constituted to study the question of extending Central Industrial Security Force to cover the requirements of security of banks. The Committee has been asked to submit a report within three months.

Some questions were raised about eve-teasing and we have made certain provisions, here. The police personnel are deployed at girls' schools and colleges, bus-stops and cinema-houses. Surveillance is kept on known criminals and action under normal preventive sections of Cr. P. C. is taken against bad characters and criminals. Any crime committed against even a single woman is a shame on our society and we, on our part, would not spare any effort to uphold the dignity and honour of the women and to put down any atrocity on them.

The incidence of unnatural deaths including dowry deaths has been, unfortunately, very high and when this matter was brought to notice, our Home Minister took very quick action. With a view to investigating into complaints of deaths or suicides of women arising out of disputes about dowry, the Crime Branch of Delhi Police has set up a Special Cell to receive complaints and investigate into them.

So far as the Dowry Prohibition Act is concerned, there is already a Joint Select Committee which has been constituted under the chairmanship of our Hon. Member of this House, Smt. Krishna Sahi. All these matters are being looked into by this committee. About suicides, instructions have been issued to police officers to take serious notice of all cases of suicide or death in suspicious circumstances of young married women. The cases are treated as special report case and the investigation should be conducted by an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police (Assistant Commissioner of Police).

Instructions for getting the post-mortem conducted by at least two doctors in dowry death cases have been issued. However, doctors are required to do the necessary certification and attestation at the time of recording of the dying declaration. Special Megistrate have been detained for regarding the dying declaration in such cases.

Sir, I have also said during the course of the call attention, that we are thinking of introducing Coronery system in Delhi to have a speedy enquiry of these cases and see that justice is meted out.

About the working of Tihar Jail, in the morning itself, while replying to a supplementary, we have said that we are taking all steps to see that some more buildings are constructed for putting prisoners and segregating women prisoners and also juvenile delinquents and other hardened criminals. This is being done and our Home Minister made a surprise visit to these places and studied these things for himself and has given clear instructions.

About overcrowing also, steps have been taken to move 158 long-term prisoners to Jails outside Delhi. These are the various steps that are being taken.

About the 20-point economic programme, I may mention a few points, and also I am coming to the Services. This is the most important subject so far as Services are concerned. We have taken several steps by adopting the Kothari Committee Report of the U. P. S. C.

where the candidates have been given facility to answer in any language listed in the VIII Schedule. The papers are set in Hindi and English. *Viva-voce* marks are also reduced. We are trying to attract more people from rural areas to compete successfully for this examination. Yesterday, my friend has also elaborately dealt with the manner in which the reservations for scheduled castes and tribes have been made. Where they are wanting in certain things, special coachings are being conducted.

Another important matter which I wanted to bring to the notice of Hon. Members is with regard to new All-India Services. There is a proposal before the Government to constitute two new All-India Services, that is, the All-India Engineering Service and the All-India Health Service. We are seeking the concurrence and the consent of the various State Governments.

About the rural-oriented services, special emphasis is being given to re-orient the conditions of services who work in rural areas. We have taken it up very seriously because we know, in most of the cases, the Plan outlays, the amounts allotted during all these Plans, are not being properly spent. For the infrastructure to be developed, in so far as the services are concerned, we have to implement the programmes and policies by utilising the funds more constructively and usefully for the welfare of rural people. We want a re-orientation of the rural services. The Planning Commission has taken it up. We have taken it up with the State Governments, we are asking for their consent in this matter. Unfortunately, only a few State Governments have come up with their proposals. We would like to have guidelines to see that more personnel are attracted to rural areas because there are several problems facing the personnel who are in-charge of developmental activities. So, they are not willing to go and serve in the villages. That is also very much under the consideration of the Government.

My Hon. friend, Dr. Farooq Abdullah, said about corruption. I only humbly request the Hon. Members not to create an impression that the entire country is seething with corruption; that our entire society is debased and that everybody is a corrupt man. This is not the way in which we have to tackle the problem of corruption.....

DR. FAROOQ ABDULLAH: On a point of order. Sir. I have not said that everybody is corrupt.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I am saying generally, not about your speech only.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you say, everybody, it will be including yourself. You will not say like that.

SH. P. VENKATASUBBAIAH: Our endeavour has been, as our Prime Minister has rightly said, to wage a relentless war against this disease of corruption.

We have provided certain amenities, certain financial incentives, in the recent Budget to make our officers fully contented. We have taken several steps; we are giving them some gratuity and we have also made some amendments in pension rules. We are trying to keep them contented.

The Central Vigilance Commission is already there to go into the misconduct of public servants. The Central Bureau of Investigation is also there. The performance of these agencies has been highly satisfactory. The Central Vigilance Commission acted on 1637 complaints out of 1676 complaints received during 1981. In 1980, action was decided on 1350 complaints out of 1637 complaints received.

As far as the Central Bureau of Investigation is concerned, in 1981,

[Shri P. Venkatasubbaiah]

1229 cases were registered by CBI as against 1194 in 1980. Out of these 1078 cases were against public servants and the remaining 151 were against private persons/firms. 288 cases were disposed of by the courts in 1981 of which 186 cases ended in conviction. Of the 580 departmental proceedings concluded during 1981, 422 cases resulted in punishment as compared to 521 cases decided in 1980.

Every year, annual programme of vigilance and anticorruption work is chalked out by the CBI in consultation with the CVC. The Programme envisages concerted action by selected Departments and Public Sector Undertakings in collaboration with CBI. Some of the important Ministries/Departments/Undertakings selected for the Programme for 1982 are the Ministry of Railways, Income-tax Department, Central Excise and Customs, nationalised banks, LIC, P & T, Food Corporation of India, DGS&D, DDA, CPWD and Asiad Work. Special emphasis is laid on collection of information about corruption and malpractices at various levels, keeping surveillance on corruption-prone areas conducting surprise checks at selected points and places to see that corrupt persons are prosecuted and punished, according to law.

Administrative action alone will not be able to root out this disease. Public opinion has to be mobilised, In this case, there need not be any political affiliations to be taken into account nor can there be any other considerations.

As has been very rightly said by my Hon. friend Dr. Farooq Abdullah, this is a national problem. Whether it is Dr. Farooq Abdullah or I or whoever it may be, if there is at all corruption, and wherever there is corruption, we have to join hands and see that a proper climate is created so that corrupt people will not go scot-free and take the country for a ride. This is the matter which I would like to bring to the notice of Hon. Members.

There was criticism about the Public Sector Undertakings that high posts are remaining vacant for long. I would like to inform the Hon. House that posts in Public Sector enterprises remained vacant for a considerable period. Consequently, a special drive was launched in September, 1981 for the purpose of filling up the top-level vacant posts in these enterprises. As a part of this drive, the re-constituted Public Enterprises Selection Board finalised selections for 18 posts as part-time Chairmen, 37 posts of full-time Chief Executives and 46 posts of functional Directors of Public Enterprises, after holding 36 meetings of the Board about the middle of March, 1981 and middle of March, 1982.

As a result of the special drive, the number of vacant posts of Chief Executive which stood at 71 in September, 1981, has now been reduced to 10.

Most of the existing vacancies have come up recently and action is under way to fill up those vacancies.

It is hoped that the selections for these posts would be finalised shortly.

The Hon. Minister of Home Affairs will answer all the other points which have been raised by Hon. Members.

I am highly thankful to all the Hon. Members for giving me a patient hearing. The Ministry of Home Affairs has tried its utmost to cope up with the situation during this crucial period.

I assure the House that any valuable suggestion at any time coming from any quarter will be taken into consideration.

I once again reiterate that we are wedded to secularism, democracy and socialism.

Our Prime Minister and our Government are determined to put down all the obscurantist and antisocial elements whether they are Muslim communalists, Hindu communalists or whatever communalism is there.

Some people have said that these organisations have to be banned. Will we be able to achieve our purpose by banning these organisations, unless we fight them politically ? Administrative action alone is not enough. We have to fight them politically and mobilise secular forces in the country to see that these forces are driven out and rooted out.

In this noble task, I hope that every political party will give its utmost cooperation to our Prime Minister to see that those obscurantist forces which are posing a threat to the secular character of our country and which are trying to destabilise the democratic traditions of this country, are thrown out completely.

I hope that all the Hon. Members will support this crusade against the obscurantist and divisive forces in this country.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri G. Narsimha Reddy.

If Hon. Members from the ruling party take only 5 minutes each, then everyone........

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please listen to me. You listen to me and then, oppose it or support it.

Then I can cover all the Hon. Members. Because the Hon. Minister is going to reply at 5.15 P.M. If every Hon. Member takes only 5 minutes, at least 12 Hon. Members can speak.

SOME HON. MEMBERS : Let it be tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no. This is not in your hands. They have already decided and I have already announced.

You will have to sit late.

The allotted time is over. Mr. Narsimha Reddy. I request the Hon. Member to take not more than five minutes. Make only the points so that the Minister will be able to remember and reply to those points. Otherwise, if you make a long speech, he will not be able to reply to those points.

SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down. Your Party's time is over. Mr. Narsimha Reddy.

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad) : Today is the third day when we have been debating the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. I rise to support the Demands.

I would not like to take much time going into the details of the law and order situation in this country, but I would like to add one sentence on this. So many Hon. friends have said that, while maintaining law and order, the police forces have killed many persons in the name of encounters. Since the last 30 or 32 years, we have been seeing this. If you draw a graph of the law and order situation in the country, you will find that the situation is under the perfect control of the Government, but in spite of that, I would like to tell the Hon. Home Minister that the

[Shri G. Narsimha Reddy]

situation in general is definitely deteriorating. We should be able to give a feeling of security, a sense of security, to the people of this country because our country is a developing country. We can continue with our developmental activities only if our country has complete internal peace. This is very important—maintaining internal peace. The Home Minister has to come out with all the force at his command and give all the support to the police force; while maintaining law and order in this country, if any police force makes a mistake or commits some blunder without intention, then he must be in a position to pardon him only with the object that the forces should continue to maintain law and order in this country.

I would now like to go to one of the important subjects in the Home Ministry and that is, about tribal development. I would request the Hon. Minister to pay a little attention to what I have to say on this subject. In our book we have said that, as far as tribal development is concerned, we are envisaging to main points: one, the developmental side and the other, protecting them. For the developmental side, I agree with you that the allocation of funds has been increasing year by year : there is no doubt about it. But I would like to bring to the notice of this august House the question of implementation, whether the implementation is taking place or not. We are not paying attention to the implementation side. I represent Adilabad; we are having two tribal blocks in my constituency. I have toured a good number of times. I would like to give some examples. First of all, we have to find out whether the officers who have been posted there are committed to the developmental aspect of the tribals or not. Education, we all know, is a very important subject for the tribals. I can tell you my experience in the tribal areas of my constituency. In more than 60 per cent of schools, the teachers do not attend the schools they only draw their salary. Your allocation is there; that is all. What is the use as long as we do not take any interest to see that the tribals are benefited ? Whatever plans and programmes are there, unless they are put on the ground to the right perspective which reaches the man whom we want to give, then there is no point; you may allocate even Rs. 5000 crores but it is of no use. So, I would like to draw your attention. We cannot say that implementation is a State Government subject and keep quiet. That is not sufficient. When constitutionally we are obliged to all the tribals in this country to see that their development takes place and once we feel that it is our duty, I feel that a parliamentary committee consisting of all the MPs who represent tribal blocks should be convened once in six months at least to find out how the implementation programme is going on.

Last point I would like to touch and sit down. I hope the Hon. Minister and other Members who represent the tribal areas are aware of especially the Land Regulation Act. We are very proud and we say so many of our States have passed Land Regulation Act where land, if any, of the tribal was purchased by a non-tribal some years ago, should be taken from the non-tribal and given back to the tribal. Simply this is the objective of the land regulation Act. But in practice what is happening ? I will give you one example. In my own area the tribals who do not know that there is an Act of this type, are reminded by the officers and the Party workers and they told them that our government has passed such an Act. 'Now we are going to give you the land which has been purchased from your ancestors by non-tribals. We will snatch it away from the non-tribals and give it to the tribals.' In some cases the officers who are in charge of this task have taken over the land under the Act from non-tribals and given it to

the tribals. Those tribals who never imagined that they would get back their ancestral land and who have settled down in the interior of the forests have left that village and come over to this village and occupied the land. Then the non-tribal went to the court and has brought a stay. Probably the Home Ministry is aware of it. The High Court of Andhra Pradesh has given a judgment that the land should be given back to the non-tribals. So now the same officer—I do not know whether the Home Minister is trying to follow me—has gone to the tribal now and asked the tribal, 'This is not your land' and he has taken away the land from the tribal and given it back to the non-tribal. That is why the Tribals felt agitated and there was firing and all that in Indervalli in my constituency.

So if we really want to help the tribals of this country let us not simply pass laws and enact rules and sit here. The tribals in my district are saying, 'Why have you told us and why have you called us from the interior and why have you taken the land from the non-tribal and given it to us ? During the time we have sold away the property.' The same officer under the court order is now snatching the land from the tribal.

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : Have not the Government appealed against that judgment ?

SHRI G. NARSIMHA REDDY : What I am trying to tell you is : why you create this problem ? When you are passing a law, why don't you see that it is perfect in all respects and foolproof ? If you do not do it, it will only create problems. To-day in Adilabad district the tribals are agitated. Why do you call it a disturbed area ? Why are they disturbed ? It is only because of this type of activities which are wrongly managed and wrongly handled and the tribals are unnecessarily provoked against the Government and our Party. So I would like to appeal to the Government to correct this and see whatever we want to give them and whatever assistance we want to give the tribals, really reaches them.

श्रीमती उषा वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का पूरे तौर पर समर्थन करती हूँ।

हमारी सरकार ने देश की आंतरिक स्थिति को नियन्त्रण में रखने में शानदार सफलता प्राप्त की है, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। विरोधी पार्टियों और कुछ स्वार्थी तत्व निराधान बातों को लेकर सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार करते रहते हैं जो दुःख की बात है। विरोधी राजनीतिक दलों के पास अपना कोई कार्यक्रम नहीं है। उनका एकमात्र कार्यक्रम निरर्थक बातों को लेकर प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और सरकार को बदनाम करना है। इस बेकार की कोशिश में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी वे सबक नहीं लेना चाहते। देश में अशान्ति और उपद्रव का वातावरण बनाने में ये लोग अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। अगर इसके बदले ये लोग सद्भावना, शान्ति और राष्ट्रीय सहमति का वातावरण बनाने का रचनात्मक काम करें तो देश का भला हो सकता है।

राष्ट्रीय सहमति की आज जितनी बहुत अधिक आवश्यकता है इसके बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। कम से कम देश की जो मूल समस्यायें हैं, उन्हें हल करने में सभी वर्गों, दलों और समुदायों को सरकार से पूरा सहयोग करना चाहिए। लोकतन्त्र को इसी तरह मजबूत बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय सहमति देश की प्रगति में तेजी ला सकती है।

[श्रीमती उषा वर्मा]

विरोधी दल जिम्मेदारी की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। लोकतन्त्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का स्वस्थ विरोध तो हो सकता है, लेकिन विरोधियों की यह भी जिम्मेदारी है कि देश की प्रगति के लिए सरकार के प्रयासों में योगदान करें।

आज देश के सामने कई मूल समस्यायें हैं, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है जिसे रोकना जरूरी है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर उसे अधिक उपयोगी और देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना होगा। सार्वजनिक और निजी जीवन में नैतिकता की स्थापना करनी होगी। चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल खत्म करना ही होगा। नौकरशाही की मनोवृत्ति को जनआकांक्षा के अनुकूल बनाना होगा। विलासिता का जीवन जीने की उच्च वर्ग की मनोवृत्ति को खत्म करना जरूरी है। युवा वर्ग को अकर्मण्यता से निकाल कर कर्म के रास्ते पर चलाना है। देश की समस्याओं का हल करने में विरोधी दलों से सरकार के साथ सहयोग करने की मैं उनसे अपील करती हूँ।

हमारी प्रधान मन्त्री जी विरोधी दलों के सहयोग का हमेशा स्वागत करती हैं। वे लोकतन्त्र में महान आस्था रखती हैं। दुःख की बात है कि कई ताकतें देश के अन्दर अशान्ति और गड़बड़ी का वातावरण बनाए रखना चाहती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि ऐसी ताकतों को सख्ती से कुचलना चाहिए।

खालिस्तान जैसे राष्ट्र-विरोधी नारों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ स्पष्ट दिखाई देता है। देश की एकता के लिए ऐसे खतरों से निपटने में सरकार के साथ सहयोग करने में सभी लोगों को सामने आना चाहिए। लेकिन कुछ ताकतें आग भड़काने में लगी रहती हैं।

साम्प्रदायिक सद्‌भाव को बिगाड़ने और शान्ति से रहने की इच्छा रखने वाले समुदायों के बीच झगड़ा कराने में कुछ साम्प्रदायिक दलों की साफ-साफ साजिश होती है। मैं देश के समस्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक और देशभक्त लोगों से अपील करती हूँ कि साम्प्रदायिकता के सांप को कुचलने के लिए एकजुट हों।

राष्ट्रीय एकता समिति का नए सिरे से निर्माण कर उसे और अधिक सक्रिय बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में बुद्धिजीवियों, श्रमिकों और युवावर्ग का सक्रिय सहयोग लिया जाना चाहिए। सरकार को इस कार्य में सभी वर्गों के साथ मिल कर देश में जन-जागृति अभियान चलाना चाहिए।

साम्प्रदायिक सद्‌भाव को भंग करने की कोशिशों के पीछे भी विदेशी ताकतों का हाथ होता है। ऐसी ताकतों को सख्ती से दबाया जाना चाहिए।

हरिजनों के साथ समाज विरोधी तत्वों की हरकतों का नाम लेकर भारी कोहराम मचाया जाता है, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जात-पात हमारा सामाजिक अभिशाप है। इसका निराकरण सामाजिक क्रान्ति ला कर ही किया जा सकता है। प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि वह सामाजिक क्रान्ति की मशाल उठाये।

जात-पात राजनीतिक समस्या नहीं है, किन्तु यह राजनीतिक तब बन जाती है जब कुछ राष्ट्रविरोधी तत्व दूसरे समाज विरोधी तत्वों की निन्दनीय हरकतों का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। समस्या के मूल में

आर्थिक पहलू भी है। हरिजनों की सुरक्षा की व्यवस्था करने और उन्हें हथियार देने के साथ-साथ जब तक उनकी आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी, तब तक समस्या का हल नहीं निकल सकता। हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के मन में हरिजनों के लिये दर्द और सहानुभूति है। उन का नया बीस सूत्री कार्यक्रम हरिजन कल्याण की नई रोशनी ले कर आया है।

जब समाज विरोधी और देशद्रोही ताकतों से निपटने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और आवश्यक सेवा अधिनियम लागू किये जाते हैं तो उनके खिलाफ़ निरर्थक प्रचार किया जाता है, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि इन कानूनों का निरपराध लोगों के खिलाफ प्रयोग किया गया हो।

विरोधी दलों की हड़ताल और आन्दोलन की कोशिशों को जनता नाकाम करने लगी है। 19 जनवरी के तथा कथित "भारत-बंद" की पोल खुल गई। रास्ता रोको और चक्का-जाम आन्दोलन बुरी तरह असफल हो गये। विरोधी दलों को चाहिये कि वे अब रचनात्मक सहयोग का रास्ता अपनायें। असम की समस्या और धर्म-परिवर्तन जैसे मामले रचनात्मक सहयोग से ही सुलझाये जा सकते हैं लेकिन निहित स्वार्थी तत्व तो आग लगाने में जुटे हुए हैं। धर्म की रक्षा के नाम पर पूना, कन्याकुमारी और नगरकोयल में जो दंगे कराये गये उन के पीछे प्रतिक्रिया-वादी और साम्प्रदायिक दलों का हाथ है, जो हमेशा नया चेहरा लेकर सामने आते हैं। विश्व हिन्दू परिषद साम्प्रदायिकता के सांप का ऐसा ही नया अवतार है।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में डकैतों का तेजी से सफाया हो रहा है। दुख की बात है कि डकैतों को मरते हुए देख कर कुछ विरोधी दल फर्जी मुठभेड़ों का भूत खड़ा करते हैं। पुलिस के बहादुर जवान और अधिकारी शहीद हो कर डकैतों का उन्मूलन कर रहे हैं। पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिये सिपाहियों और छोटे अफसरों की आर्थिक दशा में सुधार करना चाहियें और उन्हें अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये। मैं सरकार से अपील करती हूं कि सभी राज्य सरकारों को पुलिस के सिपाहियों और छोटे अधिकारियों के वेतन और सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये प्रेरित किया जाय।

सिपाहियों की तनख्वाहें बहुत कम हैं। सुविधाएं भी बहुत कम हैं। उनके कठोर कर्त्तव्यों को देखते हुए उनका आर्थिक उत्थान करना जरूरी है।

अन्त में मैं फिर एक बार सभी देशभक्त लोकतांत्रिक ताकतों से हमारी महान् नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत करने की पुरजोर अपील करती हूं। विरोधी दल अपनी एकता की असफल कोशिशों में लगे रहते हैं। उन्हें चाहिए कि विरोधी एकता की मृगतृष्णा के पीछे भागना छोड़ कर वे राष्ट्रीय एकता का दामन पकड़ें। उनका भी कुछ उद्धार हो जाएगा।

अन्त में मैं भारत के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों की मांगों का समर्थन करते हुए गृह मंत्री जी से अपील करती हूं कि केन्द्रीय पार्लियामेंटरी परामर्शदात्री समिति द्वारा पास की गई सभी मांगों को गृह मंत्री जी अतिशीघ्र अपनी केबिनट से मंजूर कराएं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Laxman Karma.

SHRI ERA MOHAN : Sir, I want some time. (*Interruption*)

MR. DEPUTY SPEAKER : There will not be time. Please listen. This is not correct procedure. I am asking you to sit down.

श्री लक्ष्मण कर्मा (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। इससे निश्चित रूप से आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

प्रधान मंत्री जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया है, उससे द्रुत गति से विकास होगा और इस कार्यक्रम से आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्गों के लोगों का उत्थान होगा। इससे हमारे जो पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको लाभ होगा। इसलिए हमारे देश की प्रधान मंत्री ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

आई० आर० डी०, एन० आर० ई० पी०, ट्राइसम और जो दूसरे प्रोग्राम गरीबों के लिए शुरू किये गये हैं, उनसे आदिवासी और गरीब तबके के लोगों को और देहात में रहने वाले जो लोग हैं, उनको काफी लाभ होगा लेकिन इस कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कर्मशियल बैंक सामने नहीं आ रहे हैं और बिना बैंकों की सहायता के ये काम नहीं हो सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आदिवासी और हरिजनों के उच्चाधिकारी, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० या न्यायिक सेवा में जो जज हैं, वे बहुत कम हैं और यह देखा जाता है कि हमारी जो आरक्षण नीति है, वह कारगर रूप से लागू नहीं की जा रही है। हमारे देश में आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और जजों में आदिवासियों को भी अवसर मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय इस तरफ ध्यान दे और इन लोगों को भी अवसर दिया जाए।

विरोधी दल हमेशा हवा में बात करते हैं और बार बार नेता बदलने की बात करते हैं। मेरा कहना यह है कि विकास के लिए एक नेता, एक पार्टी एक झंडे की जरूरत है। हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एक ऐसी नेता हैं, जो हरिजनों और आदिवासियों की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं और उनके लिए नये नये कार्यक्रम चला रही हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम अभी चालू किया गया है और इस से इन लोगों को बहुत अधिक लाभ होगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में, बस्तर जिले में नक्सेलाइट्स की गतिविधियां बहुत जोरों से चल रही हैं और इस से वहां पर आदिवासी काफी आतंकित हो रहे हैं। कृपया इस तरफ ध्यान दिया जाए और पुलिस बल वहां पर रखा जाए ताकि इस चीज को रोका जा सके। उन के लिए निर्माण कार्य और विकास कार्य कराए जाएं, ताकि उनको मजदूरी मिल सके। इस से वहां के लोगों को ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है। वहां पर रोज नक्सलपंथियों का आतंक बना रहता है। इसलिए वहां पर नये विकास कार्य द्रुत गति से चलाने की आवश्यकता है। बस्तर जिले में अबूजमार्ग एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर प्रिमिटिव लोग रहते हैं और उन के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं लिया गया है। वह एक अपेक्षित क्षेत्र है। वहां पर

विकास कार्य तथा दूसरे कार्य करना बहुत आवश्यक है तभी वहां के आदिवासियों को लाभ मिल सकेगा, आगे बढ़ सकेंगे।

पिछड़े लोगों तथा आदिवासियों का ठेकेदार बहुत अधिक शोषण करते हैं। अधिकारी लोग भी करते हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसी समितियां वहां बनाई जाएं जो यह देखें कि आदिवासी क्षेत्रों में ठेकेदार या अधिकारी वर्ग आदिवासियों का शोषण न कर सके और उनको न्यूनतम मजदूरी दिलाएं।

आदिवासी, हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोग अधिकांश में अशिक्षित हैं। उनको शिक्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहियें। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाने चाहियें। प्रौढ़ शिक्षा की जो योजना है, जो कार्यक्रम है इसको प्रभावशाली ढंग से, कारगर ढंग से लागू किया जाना चाहिये। उनको इस योग्य बनाया जाना चाहिये कि वे शोषण से बच सकें।

बस्तर जिले के वनों में आदिवासी लोग रहते हैं। विकास के कार्यक्रम वहां बहुत कम चलाए गए हैं। उनको इन से लाभ नहीं मिल रहा है। वहां पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव है कि विशेष सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये।

आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं। उनका जंगलों में काम करने वाले ठेकेदार बहुत शोषण करते हैं। उनके शोषण से आदिवासियों को बचाने के लिए वहां पर कमेटियों का निर्माण किया जाना चाहिये। वनों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए वहां सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिये। उनकी उपज की खरीद की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। सीधे उसको खरीदा जाएगा तभी उसको शोषण से बचाया जा सकता है।

रिजर्वेशन की अवधि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने दस साल के लिए बढ़ाई है। इस अवधि में तीव्र गति से उनके विकास के लिए काम किए जाने चाहियें, कारगर ढंग से उनके वास्ते जो कार्यक्रम हैं उनको चलाया जाना चाहिए। ऐसा किया गया तभी उनका विकास सम्भव हो सकेगा।

बस्तर पिछड़ा जिला है। आवागमन के साधन वहां बहुत कम हैं। इससे बड़ी असुविधा होती है। आदिवासी इलाकों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिये। इससे वहां लोगों को काम मिलेगा। आवागमन की कमी की वजह से वहां विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

धन्यवाद।

डा० हीरालाल आर० परमार (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, दलित वर्ग की जो असली बीमारी है उसकी ओर मैं इस सदन के डाक्टरों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा देश आजाद है। दलित वर्ग के लोग आज भी रूलिंग पार्टी कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए कुछ कर भी रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं कर रही है। फिर भी जो बीमारी है उस बीमारी की तरफ सदन के डाक्टरों का मैं ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं।

[डा• हीरा लाल ग्रार परमार]

गुजरात गांधी जी का प्रान्त है ग्रौर मैं वहीं से ग्राता हूं। वहां की समस्याग्रों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। गुजरात में किसी भी गांव में एक भी मंदिर में कोई दलित नहीं जा सकता है। ग्राज तक नहीं जा सका है। गुजरात में तालाब से गधा पानी पी सकता है लेकिन दलित नहीं। वह उसके नजदीक नही जा सकता है। मैं चैलेंज के साथ यह बात कहता हूं। गुजरात में किसी भी मंदिर में दलित नहीं जा सकता है, किसी भी कुए पर, किसी भी तालाब पर नहीं जा सकता है। 33 साल की ग्राजादी के बाद भी यह हालत है। यह एक तथ्य है। डाक्टरों के सामने मैं यह समस्या रख रहा हूँ।

बीस सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के ग्रनुसार देहातों में दलितों को प्लाट देने की बात कही गई है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि गुजरात में किसी भी गांव में दलितों को प्लाट गांव के ग्रन्दर नहीं दिया जाता है, गांव से दूर ग्रौर ग्रलग दिया जाता है। ग्राजादी के 33 साल के बाद भी यह समस्या है।

एक बात ग्रौर है कि न्यायालय हमारे देश में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का तन्त्र क्या काम कर रहा है? उदाहरण के लिये कफालता में 2 साल पहले एक दलित नौजवान की बारात जा रही थी, दूल्हा बेचारा घोड़े पर बैठा था, बाजे बज रहे थे, तो उच्च जाति के लोगों ने 14 बारातियों को मार दिया था ग्रौर पुलिस ने ऐसी कार्यवाही की कि ग्रदालत से सब लोग निर्दोष छूट गये। लेकिन दिल्ली में दो साल पहले चोपड़ा परिवार के 2 बच्चों को मार दिया था, कातिलों का पता भी तब नहीं था, लेकिन पुलिस ने इतनी मुस्तैदी से कार्यवाही की कि दो कातिलों को, बिल्ला ग्रौर रंगा को- फांसी दी गई। लेकिन दलितों वाले केस में ग्रदालत से 14 ग्राद-मियों को मारने वाले साफ छूट गये। ग्राज हमारी ही बनाई हुई सरकार है, हम ग्राशा करते हैं कि हमारी सरकार हमारे लिये कुछ करेगी। इसी तरह से 219 हमारी हाउसिंग-कोग्रापरेटिव स्कीम हैं, रूरल हाउसिंग की जो 7 साल से स्थगित हैं। एक मिनिस्टर का या क्लास 1 ग्रफसर का संडास ग्रौर बाथरूम बनाने पर 12, 15 हजार रु० खर्च किया जाता है, लेकिन दलितों के लिये पूरा मकान 3,000 रु० में बनाया जा रहा है। ग्राप सोचें इतने कम पैसों में ग्राजकल क्या मकान बन सकता है? यह ऐस्टीमेट 1956 में बनाया था लेकिन ग्राजकल की महंगाई को देखते हुए उस में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसी तरह से रिजर्वेशन हमको उठाने के लिये रखा गया। फिर भी गुजरात में 7 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को नहीं लिया जाता है। किसी टीचर की पोस्ट के लिये विज्ञापन निकलता है, 2000 दरखास्तें ग्राती हैं, लेकिन 7 प्रतिशत से ज्यादा दलितों को नहीं लिया जाता है। तो यह रिजर्वेशन है या कन्ट्रोल है?

मैं पब्लिक ग्रन्डरटेकिंग कमेटी का सदस्य हूँ ग्रौर इस नाते देश में उनकी स्थिति को देखता हूँ। स्वीपर का काम हमारे लिये ही हैं, ब्राह्मण, पटेल, बनिये का नहीं है। मैंने बम्बई में देखा कि स्वीपर्स को कांट्रेक्ट पर रखा जाता है एयर इन्डिया ग्रौर इन्डियन एग्ररलाइन्स में वहां बम्बई में 450 स्वीपर्स काम करते हैं 6 रु० डेली वेजेज पर। मैंने दारुवाला कांट्रेक्टर को लिखा कि इतनी कम पगार

में कैसे कोई काम कर सकता है। लेकिन काई सुनने वाला नहीं है। 30, 35 किलोमीटर से वह गरीब काम पर आता है। 2 रु० तो उसके बस में खर्च हो गये। 4 रु० में वह कैसे अपना पेट पाल कर सकता है? हम चाहते हैं कि बनिया, ब्राह्मण इस काम में आयें, मुमकिन है तब पगार बढ़े।

डा० अम्बेडकर दलितों के माने हुए नेता हैं उनकी मूर्ति संसद भवन में लगी हुई है जहां उनके जन्म दिन पर उत्सव होता है। लेकिन अम्बेडकर स्टेडियम में उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया था, उसको ठीक करने के लिए आन्दोलन भी हुआ। लेकिन वह मूर्ति आज तक नहीं बनी। तोड़ने वालों को कुछ सजा नहीं दी गई। किसी अन्य बड़े नेता जैसे सरदार पटेल या जवाहर लाल जी की मूर्ति होती और वह टूट गई होती तो क्या होता? तोड़ने वालों को सजा भी मिलती और मूर्ति भी बन गई होती। लेकिन डा० अम्बेडकर की मूर्ति आज तक नहीं बनी है। हमें साल में एक बार ही होम मिनिस्ट्री की डिमान्ड पर बोलने का मौका मिलता है। तो हमारी आत्मा को क्या कंट्रोल कर सकते है? मैं 17 करोड़ दलितों का प्रतिनिधि होने के बाद इस सदन में उनकी दर्द की बात नहीं बताऊंगा तो इलाज कैसे होगा?

मैं डाकुओं की बात कहना चाहता हूं। डाकू डाका डालने गये देहुली में, साधोपुर में, केस्तरा में। वह किस के घर डाका डालने गये? जिसके घर मिट्टी के फूस के बने हुए हों, पहनने को कपड़े न हों, खाने को अनाज न हो तो उनके यहां लुटेरे क्यों जाते हैं? इसके कारण में डाका डालना नहीं है, वह कारण हमें देखना होगा।

दलित लोग मुसलमान होते हैं, क्यों मुसलमान होते हैं वह भी देखें कि इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? हमारे देश का यह सदन बिना साम्प्रदायिक है, यहां किसी धर्म की बात कर सकते हैं तो इस बात के चिल्लाने की क्या जरूरत है कि दलित मुसलमान हो रहे हैं। अगर कोई सिख, पारसी, बुद्धिस्ट हो तो कोई चिन्ता नहीं होती है लेकिन अगर कोई दलित मुसलमान होता है तो चिन्ता है। यह क्यों?

मुसलमानों और दलितों का 5,000 साल से क्या सहयोग है, यह पुरानी बात है, मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। आप सब को पता है कि कि गांव में दलितों का घर कहां होता है। उनका घर गांव के पूर्व भाग में होता है और मुसलमान का घर भी दलित के घर के पास होगा। यह हमारा उनसे सहयोग रहा है जो कि हजारों साल से चला आ रहा है। हमारे हिन्दुस्तान के मुसलमान हमारे भाई हैं, अगर देश के 15 करोड़ दलितों से वह सहयोग करें तो उसमें क्या बात है?

श्री माधव राव सिन्धिया : (गुना) हम भी आपके भाई हैं।

श्री हीरा लाल आर० परमार : हमारे गृह-मंत्री शेर बोला करते हैं, मैं भी एक शेर कहना चाहता हूं :—

सचाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से ॥

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इन दलित लोगों का ख्याल करना चाहिए। इनकी आबादी 15 करोड़ के बाद भी इनके लिए अलग मिनिस्ट्री और अलग मिनिस्टर नहीं

[डा० हीरा लाल आर० परमार]

बनाया जाता है। रिजर्वेशन में स्वीपरों के लिये आज एन्टी रिजर्वेशन आन्दोलन होता है। अब अगर मुसलमान वह हो जाते हैं तो रिजर्वेशन आटोमेटिक खत्म हो जाता है। अगर वह मुसलमान हो जायें तो रिजर्वेशन खत्म, यह भी देखना जरूरी है, इससे आपको फायदा होगा। हरिजन अगर मुसलमान होगा तो यह सवाल पार्टी का नहीं है, यह सब का सवाल है। अगर हरिजनों के लिये गंभीरता से कुछ नहीं सोचेगें तो आज देश में दलित जागरूक हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि 3 साल का बच्चा अपनी मां की गोद में सो सकता है, लेकिन 35 साल का बच्चा होने के बाद अगर कोई कहे कि मां के साथ सो जाओ तो वह उसका सिर तोड़ देगा, खामोश नहीं रह सकेगा। देश के दलित आज पैंतीस साल के जवान हो गए हैं।

उपाध्यक्ष जी, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में सत्तारूढ़ दल के अनेक सदस्यों ने विरोधी दलों से सहयोग की बात कही है। सहयोग के साथ आरोप भी लगाये गये हैं।

गुजरात में जब आरक्षण का आन्दोलन हुआ और आन्दोलनकारी सड़कों पर निकल आये, सारे समाज की एकात्मता के लिए खतरा पैदा हुआ, तो क्या इस सदन में विरोधी दलों ने सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित नहीं किया?

अगर हम चाहते, तो आरक्षण पर होने वाले आंदोलन का दलगत लाभ के लिए प्रयोग कर सकते थे। (व्यवधान) श्री मनीराम बागड़ी विरोध में किसी से कम नहीं हैं, मगर सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित करने का सुझाव श्री मनीराम बागड़ी की ओर से ही आया था जो सब से उग्र विरोधी हैं, उनका भी दृष्टिकोण रचनात्मक है, इस पर जोर देने के लिए मैं यह कह रहा हूं।

16.56 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJI *in the Chair*]

आसाम में विदेशियों के सवाल को हल करने के लिए विरोधी दल त्रिपक्षीय वार्ता में बैठे हैं। आप शासन में हैं, सिर-दर्द आपका है, आसाम में आग लगती है, तो लगे। मगर हम यह रवैया नहीं अपना सकते। हमें चिन्ता है, और इसी लिए इस समस्या का एक संतोषजनक हल निकालने के लिए विरोधी दल अपना सहयोग दे रहे हैं।

राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने के लिए सब के सम्मिलित प्रयत्न हों, यह आवश्यक है। मगर इसके लिए वातावरण कहां है? क्या प्रधान मंत्री के लिए यह जरूरी था कि अपने नये बीस-सूत्री कार्यक्रम को देश के सामने रखते हुए वह जनता सरकार की उपलब्धियों को घटा कर बताने की कोशिश करतीं? उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनता सरकार के दो सालों में देश बिखरने वाला था। जनता सरकार के दो सालों में खालिस्तान का नारा नहीं लगा था। उन दो सालों में मीनाक्षीपुरम का कांड नहीं हुआ था।

श्री माधवराव सिन्धिया : उस वक्त रैसपांसिबल आपोजीशन था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कैसा रैसपांसिबल आपोजीशन था, इसका भी हमें पता है। सरकारी पार्टी जहां पर

आपोजीशन में है, वहां वह किस तरह रेंसपांसिबल तरीके से व्यवहार कर रही हैं, यह भी हम देख रहे हैं।

व्यवहार के मानदंड अलग अलग नहीं हो सकते। अभी जम्मू-कश्मीर की चर्चा हो रही थी। लद्दाख और जम्मू के साथ जो भेदभाव हुआ है, उसके विरुद्ध हम भी आवाज उठाते रहे हैं। मगर क्या लद्दाख और किश्तवाड़ में हिंसात्मक आंदोलन को उभाड़ा जाएगा? कलकत्ता में सूचना मंत्रालय ने फिल्मोत्सव का आयोजन किया, मगर नेताजी सदन में हुल्लड़ मचाने के लिए सत्तारूढ़ दल का एक नौजवान दल उठा था। अगर हम ऐसा करते, तो हम ध्वंसात्मक हैं, हमारा लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मगर लद्दाख में सरकारी दफ्तरों में आग लगेगी, कलकत्ता में बसें जलाई जाएंगी, क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ने के कारण किराये बढ़ाए गए, फिल्मोत्सव में आपके समर्थक नौजवान हुल्लड़ करेंगे, तब कोई उसकी निन्दा भी नहीं करेगा।

1947 के बाद इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमने एक नैशनल कानसैनसस ईवाल्व किया था। उस कानसनसस ने आज तक देश को एक रखा है। मुझे दुख है कि वह आम सहमति टूट रही है। दलित वर्ग आज अन्याय के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। मैं अपने हरिजन भाइयों की पीड़ा समझता हूं। मीनाक्षीपुरम में उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें जमीन नहीं दिला सकते, नौकरी नहीं दिला सकते, मगर कम से कम हमें गाली दे कर बुलाना तो बन्द कर दें। आज हम उन्हें गाली दे कर बुलाना भी बन्द नहीं कर सके हैं।

जनता पार्टी के राज्य में हरिजन भाइयों पर ज्यादतियां होती थीं, तो वे ज्यादतियां थी। क्या आज वे ज्यादतियां नहीं हैं? क्या उस समय आपने उन ज्यादतियों से लाभ उठाने की कोशिश नहीं की; बेलछी और नारायणपुर की घटनाओं को लेकर आपने विरोधी दल की सरकारों को कठघरे में खड़ा कर दिया था। प्रधान मंत्री स्वयं नारायणपुर गई थीं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में विरोधी दल की सरकार हैं, क्या आप राजनैतिक फायदा उठाने के लिए आई हैं।

17 hrs.

प्रधान मंत्री का जबाव था अगर हमारे विरोधी गल्ती करें तो हम फायदा क्यों न उठायें। अब स्थिति बदल गई है।

मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हरिजन और वनवासियों के साथ न्याय के सवाल पर एक राष्ट्रीय मतैक्य की आवश्यकता है। गृह मन्त्री नेशनल इन्टिग्रेशन कोंसिल की बैठक इसी सवाल पर विचार करने के लिए बुलायें। एक समयबद्ध कार्यक्रम तय किया जाना चाहिए। अभी वेंकटसुब्बैया जी नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल की चर्चा कर रहे थे। कब से उसकी बैठक नहीं हुई है? उसे बना दिया और अलमारी में सजा दिया। एक कमेटी आन कम्युनलिज्म बनाई गई है। (व्यवधान) उसमें मैं नहीं हूं, चन्द्रशेखर जी भी नहीं हैं। विरोधी दल से लिया गया था चव्हाण साहब को - अगर मैं गल्ती नहीं करता तो क्या उस कमेटी ने किया है? आंकड़े देकर आप सिद्ध कर सकते हैं कि साम्प्रायिक घटनायें कम हो गई हैं, लेकिन कन्या कुमारी में जो कुछ हुआ है वह खतरे की घंटी है। अभी तक देश के किसी भाग में ईसाई और हिन्दुओं के बीच में इस तरह

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

की कटुता पैदा नहीं हुई थी। मैं आरोप नहीं कर रहा और प्रत्यारोप से इसका जवाब नहीं मिलेगा। आज किसी व्यक्ति का भविष्य दांव पर नहीं लगा है, किसी दल की तकदीर आज तय होने नहीं जा रही है, अगर कोई चीज़ दांव पर है तो देश की एकता और देश की अखण्डता दाव पर है, देश की एकता और देश की अखण्डता कैसे बचेगी ?

सभापति जी, मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर एक ब्राड नेशनल कन्सेन्सस इवाल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। मगर इसके लिए जो डिमोक्रैटिक इंस्टीट्यूशन्स हैं उनकी मर्यादा की रक्षा करनी होगी। राज्यपाल हमेशा ऐसे फैसले करे जो सत्तारुढ़ दल के हक में जायें तो राज्यपाल की संस्था का सम्मान आप बनाए नहीं रख सकते हैं। केरल में क्या हुआ और असम में क्या हुआ ? असम की विधान सभा आपने भंग करदी। मुझे भविष्य के लिए चिन्ता हो रही है। . अब असम में आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। इसलिए अभी तक असम में विधान सभा को सस्पेन्ड किया जाता था, भंग नहीं किया जाता था। अभी वहां विदेशियों का सवाल तय नहीं हुआ है लेकिन राज्य सभा में कहीं विरोधी दल का एक सदस्य न आ जाए इसलिए विधान सभा तोड़ दी। केरल की विधान सभा भी अभी कुछ दिन रह सकती थी। राज्य सभा के एक एक सदस्य के लिए जो लड़ाई हो रही है, उसी से मेरे मन में आशंका पैदा हुई है कि कहीं संविधान के बुनियादी परिवर्तन की योजना तो नहीं बन रही है ? गृह मन्त्री इसका खण्डन करें।

मेरा निवेदन है कि पहले भी एक गवर्नर्स के सम्मेलन में राज्यपालों के लिए आचार-संहिता बनाने की बात कही गई थी। आप कह सकते हैं कि आप सरकार में थे तब यह क्यो नहीं किया लेकिन हमको लोगों ने इसीलिए हटाया है कि आप हमसे कुछ अच्छा करके दिखायेंगे। हम दल-बदल के खिलाफ कानून नहीं बना सके, बनाना चाहते थे लेकिन हमारे दल के कुछ लोग दल-बदल करने की बात कर रहे थे इसीलिए कानून नहीं बना लेकिन आपको क्या आपत्ति है ? मैं गोवा गया था। गोवा में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस (आई) का कोई प्रतिनिधि नहीं चुना गया था, सभी कांग्रेस (यू) के चुने गए थे और अब वहां पर सरकार है कांग्रेस (आई) की। रातों-रात उसका पुनर्जन्म हो गया। अगर गोवा में आपकी सरकार न होती तो क्या आसमान टूट जाता ? मगर नहीं, एक असहिष्णुता की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। विरोधी दलों का सहयोग चाहते हैं मगर चुनाव के लिए तैयार नहीं। मुझे दुःख है, वेंकटसुब्बैया साहब ने दिल्ली के बारे में जो कुछ कहा है, दो साल हो गए यहां मेट्रोपोलिटन कौंसिल नहीं है, म्युनिसिपल कार्पोरेशन नहीं है।

सरकारी अफसर दिल्ली की जनता की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। कोई दुखड़ा सुनने वाला नहीं है। कहां जाएं किससे अपनी बीती कहें। आज कहा जा रहा है कि दिल्ली के ढांचे के बारे में हमें नए सिरे से विचार करना होगा। दो साल तक विचार की प्रक्रिया क्यों बन्द पड़ी थी ? विचार चलने दीजिए और चुनाव भी कराइए। विशेषज्ञ समिति बन रही है, मगर उस को टर्म्स आफ रिफ्रेंस क्लीयर नहीं है। श्री टाईटलर कह रहे थे कि हमने वायदा किया है कि हम एसेम्बली बनायेंगे—वायदा किया है तो पूरा करिए। वायदा किया है तो निभाना पड़ेगा। ज्ञानी जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे प्रेरणा आ रही है। मगर

विशेषज्ञ समिति के सामने कोई रिपोर्ट दाखिल करने की सीमा-रेखा तय नहीं की गई, समय-रेखा तय नहीं की गई।

कब तक विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट देगी ? पुरानी दिल्ली के लिए आप कमेटी बना रहे हैं और बाकी दिल्ली के लिए ? मैं भी दिल्ली से चुनकर आया हूँ। मगर संसद सदस्य के नाते मुझे भी विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। उपराज्यपाल कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के मैम्बरों को साथ लेकर इलाके का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उपराज्यपाल मेरे साथ नहीं आयेंगे।

सभापति महोदय, दिल्ली का हाल क्या है ? दिल्ली में बस सर्विस घाटे में चल रही है। 1979-80 में 17 करोड़ रु० का घाटा 1980-81 में 45 करोड़ रु० का घाटा, हो गया, 1981-82 में 60 करोड़ रुपए का घाटा, जबकि बसें 2,626 हैं, जिनकी कुल कीमत 40 करोड़ रु० है और घाटा हो रहा है 60 करोड़ रु० का। फिर भी यात्रियों को सुविधा नहीं है।

डेसू की क्या हालत है ? 1978 में जनरेशन में डेसू का हिन्दुस्तान में दूसरा नम्बर था। 200 मैगावाट एव्रेज पर-डे, लेकिन अब डेढ़ सौ रह गया है। घाटा 1979-80 में 13 करोड़ रुपया, 1980-81 में 38 करोड़ रुपए, 1981-82 में 50 करोड़ रुपए और जून, 1980 से डेसू का कोई जनरल मैनेजर नहीं है। उस दिन मेरे मित्र, श्री भगत जी ने यह सवाल उठाया था। दिल्ली केन्द्र के अधीन हैं। दिल्ली में विधान सभा नहीं है। दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी आफ अथारिटीज हैं। पार्लियामेंट में दिल्ली के मामले में प्रतिबिम्बित नहीं हो सकते हैं। एक जनरल मैनेजर नियुक्त करने में आप क्यों देरी कर रहे हैं? मगर दिल्ली—दिल्ली की चिन्ता किसको है।

नतीजा यह है कि दिल्ली का राशन कम कर दिया गया है। 1978 में 20 किलो गेहूँ पर-हैड मिलता था, 1980 में 12 किलो रह गया और 1982 में 10 किलो रह गया। मजदूरों को खाने के लिए गेहूँ चाहिए, लेकिन मजदूरों को चावल दिया जा रहा है। कर्नाटक से शिकायत आ रही है कि वहां लोग चावल मांगते हैं, लेकिन गेहूँ दिया जा रहा है। सरकार दावा करती है कि रिकार्ड प्रोडक्शन है, तो फिर राशन को कम करने की क्या जरूरत हैं ?

मैंने सुना है कि दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने यह रिपोर्ट भेजी है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए अभी चुनाव नहीं कराए जा सकते। मैं चाहता हूँ कि लैफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट को सदन के टेबिल पर रखा जाए। दिल्ली में चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं ? क्या इसलिए कि आप को पराजय की आशंका है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : हमारी जीत होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो करा लो।

गढ़वाल में चुनाव नहीं होंगे। असम की 12 लोक सभा की सीटें खाली हैं। असम के मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करने का मौका नहीं मिलेगा। चुनाव जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में होने हैं। सभापति महोदय ये जानते हैं कि इन राज्यों में हालत अच्छी नहीं रहेगी।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]
इसलिए कर्नाटक को भी नत्थी किया जा रहा है और आंध्र में भी चुनाव की चर्चा चल पड़ी है।

श्री वेंकटसुबैया जब बोल रहे थे तो मैंने उन्हें टोका था। वे भी मुख्य मन्त्री बन कर आन्ध्र जाना चाहते थे हमारे साथी अंजैया साहब थे, केन्द्र में भले थे, राज्य मन्त्री थे, जब आन्ध्र जाने लगे तो मैंने पूछा, "आन्ध्र क्यों जा रहे हैं ?" कहने लगे, "हमारी तरक्की हो गई है।"

एक माननीय सदस्य : आप की नजर लग गई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस दिन मैंने कहा—तरक्की नहीं, टरक्की हो रही है।

उन को किस तरह से निकाल दिया गया? मुख्य मंत्री के पद की गरिमा नहीं रह गई है। मुख्य मंत्री आप के ही दल का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को बेइज्जत करने में आप अगर अपने अधिकार का उपयोग करेंगे तो मुख्य मंत्री की संस्था को दुर्बल करेंगे। उन्हें हटाने का और भी तरीका हो सकता था। आन्ध्र की एक सभा में मैंने भाषण में कह दिया कि मुख्य मन्त्री को चपरासी की तरह से हटाया जा रहा हैं। तो एक चपरासी ने मुझे प्रोटेस्ट-लेटर लिखा। उसने कहा—आप हमारी तुलना मुख्य मंत्री से कैसे कर रहे हैं ? हम परमानेंट हैं. मुख्य मंत्री टेम्परेरी है। हमें कोई बिना-शो-काज-नोटिस के नहीं निकाल सकता। मुझे माफी मांगनी पड़ी। सामाजिक रूप से मैंने कहा—"मैंने चपरासियों का अपमान किया है, मैं माफी मांगता हूं।"

भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा हो रही है। जो सत्ता में हैं उन्हें जवाब-देह होना है। अन्तुले को तब तक नहीं हटाया गया, जब अन्तुले का मामला सदन में आया, अदालत ने अन्तुले को हटाया। लेकिन भ्रष्टाचार केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, उसका एक नैतिक पहलू भी है। कई प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों और वहां की सरकारों के खिलाफ राष्ट्रपति और राज्यपालों को भ्रष्टाचार के अभियोग-पत्र दिये जा रहे हैं। मगर उन अभियोग-पत्रों के साथ केन्द्र में क्या खिलवाड़ हो रहा है—इसका मैं एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं।

9 दिसम्बर, 1981 को एक अन-स्टार्ड क्वेश्चन था, जिसका श्री वेंकटसुबैया ने जवाब दिया। वह मध्य प्रदेश के विधायकों द्वारा वहां की सरकार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में था। श्री वेंकटसुबैया ने कहा :—

> "श्री सुन्दरलाल पटवा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में दिये गये आरोपों को निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार टिप्पणी के लिये मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री को भेजा गया था, जो कुछ दिन पहले प्राप्त हो गई है और उन की जांच की जा रही है।"

यह 9 दिसम्बर, 1981 का श्री वेंकटसुबैया का जवाब है। मगर 8 दिसम्बर, 1981 को गृह मन्त्री ज्ञानी जैल सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर गये। उन से हवाई अड्डे पर किसी ने सवाल पूछा। सवाल यह था—"उस आरोप-पत्र का क्या हुआ ?" ज्ञानी जी ने जो जवाब दिया, वह आल इण्डिया रेडियो ने रिपोर्ट किया है, मैं बुलेटिन को उद्धृत कर रहा हूं :—

> "केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री जैल सिंह ने खण्डवा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कल एक प्रश्न के उत्तर में

कहा—प्रतिपक्ष द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह तथा उन की सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाये गये थे वे सब आरोप गलत और निराधार पाये गये।"

यह गृह मंत्री का जवाब है। 8 दिसम्बर को यह रेडियो में आया कि 7 दिसम्बर को उन्होंने खण्डवा में यह जवाब दिया है और 9 दिसम्बर को उन के ही सहयोगी, मगर कनिष्ठ सहयोगी, सदन में कहते हैं कि जांच जारी है। भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी का घरेलू मामला नहीं है।

कल बिहार के मन्त्री मण्डल के खिलाफ एक लाख लोगों ने राज्यपाल के पास जा कर एक ज्ञापन दिया है। बिहार में ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने अपने खिलाफ अपने ही आदेश से मुकदमा वापिस ले लिया है। उन पर जालसाजी का आरोप है। कौन जांच करेगा, मैं जानना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि एक सर्व-सम्मत प्रक्रिया तय कर लीजिये जो सब दलों पर लागू होगी, सब समय के लिये होगी। यह खेल अब बहुत चल चुका है कि जब हम प्रतिपक्ष में थे तब हम कुछ कहें और अब सत्ता में हैं तो कुछ कहें। आप भी प्रतिपक्ष में रह चुके हैं और फिर आ सकते हैं। कई प्रदेशों में आप आज भी प्रतिपक्ष में हैं। मगर लोकतन्त्र को बचाना है तो हिंसा का परित्याग करना होगा। एक अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सब लोगों को एक मत होना पड़ेगा और कोई आचार-संहिता बनानी पड़ेगी। क्या गृह मंत्री यह काम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जिस पद पर बैठे हैं उस के अनुरूप अपने को सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा इतिहास उनके बारे में यही लिखेगा कि उन्हें मौका मिला था; मगर उन्होंने मौका गंवा दिया।

17.15 hrs.

STATEMENT *RE.* SITUATION IN BANGLADESH

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO)) : Early this morning Lt-Gen. H.M. Ershad, Chief of Army Staff in Bangladesh announced the suspension of the Constitution, the dissolution of the Givil Administration and Parliament, and the dismissal of the President and the Council of Ministers. Martial Law has been declared over the entire country and Gen. Ershad has been declared Chief Martial Law Administrator. Other appointments in the Martial Law Administration have been made. After being introduced by former President Sattar, Gen. Ershad said on the Bangladesh Radio that this action was necessary due to the critical state of the country and economy, and that elections would be held after improvement in the situation.

According to such incomplete reports as are available to us, the situation apperas to be under control. We are in communication with our High Commissioner in Dacca and we understand that all our personnel are safe. Government are continuing to watch the situation very carefully as it develops. We consider these developments an internal matter of Bangladesh, and it is our expectation that nothing will happen which will affect our bilateral relations adversely.

We attach fundamental importance to peace, harmony and cooperation with all our neighbours and stability in the sub-continent. It is our hope that the continuing friendship and cooperation between India and Bangladesh will be maintained.